



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 2018/ज्येष्ठ 17, 1940

No. 201]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 2018/JYAISTHA 17, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2018

अंतिम जांच परिणाम

(मामला संख्या ओ. 1/09/2017)

विषय: रूस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और तुर्की के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम डाईक्रोमेट" के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच।

फा. सं. 6/4/2017-डीजीएडी:—यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटन-रोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. मेसर्स विष्णु कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे 'याचिकाकर्ता' अथवा 'आवेदक' कहा गया है) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटन-रोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार रूस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और तुर्की (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम डाईक्रोमेट" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी शुल्क की जाँच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संगत सूचना के साथ एक याचिका दायर की है।

2. और यतः, प्राधिकारी ने याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 4 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 6/4/2017-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की थी, जिसके द्वारा उपरोक्त नियमावली के उप-नियम 5 के अनुसार पाटन-रोधी जांच शुरू की गई थी, ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

क. क्रिया-विधि

3. इस पाटन-रोधी जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

- (1) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के उप-नियम 5 (5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बारे में सूचित किया था।
- (2) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 4 जुलाई, 2017 की एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की थी।
- (3) प्राधिकारी ने जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों और आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ घरेलू उत्पादकों को प्रेषित की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वे जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने लिखित विचारों से उन्हें अवगत करा दें।
- (4) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की एक प्रति भेजी थी।
- (5) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह अपने देशों से उत्पादकों और निर्यातकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत कर दें। साथ ही उन्हें उत्पादकों/निर्यातकों को प्रेषित पत्र और प्रश्नावली की प्रति, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पत्रों के साथ भी भेजी गई थी।
- (6) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

क्रमांक	कंपनी का नाम
दक्षिण अफ्रीका	
1.	(क) मेसर्ज लेनकेस सिसा प्राईवट लिमिटेड
	(ख) मेसर्ज लेनकेस (प्राईवट) लिमिटेड
रूस	
2.	मेसर्ज नोवा क्रोमे
तुर्की	
3.	(क) मेसर्ज सिसेकेम डिस टिकारेट ए.एस.
	(ख) मेसर्ज सोडा सानयाई ए.एस.
कजाकिस्तान	
4.	मेसर्ज जे. एस. अक्टियुबिन एसके क्रोमियम

(7) संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. मेसर्ज लेनकेस सिसा प्राईवट लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका
2. मेसर्ज लेनकेस (प्राईवट) लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका
3. मेसर्ज सोडा सानयाई ए.एस., तुर्की

4. मेसर्ज सिसेकेम डिस टिकारेट ए.एस., तुर्की

- (8) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

क्रमांक	कंपनी का नाम	क्रमांक	कंपनी का नाम
1.	मेसर्ज अनुपम कलर्स एक केमिकल्स	2.	मेसर्ज अनुपम कलर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	मेसर्ज स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	4.	मेसर्ज सोलर केमफर्टस प्राईवेट लिमिटेड
5.	मै. रावेशिया कलर्स प्रा.लि.	6.	मेसर्ज ए.एस. इंटरप्राइजिज
7.	मेसर्ज माईका ऑर्गेनिक्स लिमिटेड	8.	मेसर्ज सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
9.	मेसर्ज श्री वर्दयानी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10.	मेसर्ज रिद्धी फार्मा
11.	मेसर्ज वापी पिग्मेंट्स केमिकल्स एंड एल्टिड प्रोडक्ट्स	12.	मेसर्ज वापी ऑक्साईड्स एंड कलर्स लिमिटेड
13.	मेसर्ज कलर क्रोमेस प्राईवेट लिमिटेड	14.	मेसर्ज के. एन. केमिकल्स
15.	मेसर्ज इंडो टेन केमिकल्स लिमिटेड	16.	मेसर्ज शासुन केमिकल्स एंड ड्रग्स लिमिटेड
17.	मेसर्ज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती ट्राईडेंट एल्को-केम लिमिटेड)		

- (9) प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिए हैं और आयातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1.	मेसर्ज माईकाज ऑर्गेनिक्स
2.	मेसर्ज स्ट्राईड्स शासुन लिमिटेड
3.	मेसर्ज जीईई इंटरनेशनल
4.	मेसर्ज वोक्सोकोन पिग्मेंट्स एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	मेसर्ज आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
6.	मेसर्ज एश्वर्य मेकफे (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
7.	मेसर्ज कलर क्रोमेस प्राईवेट लिमिटेड
8.	मेसर्ज सोना सिंथेटिक्स प्रोडक्ट्स
9.	मेसर्ज सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
10.	मेसर्ज अनुपम कलर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	मेसर्ज अनुपम कलर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज
12.	मेसर्ज सोलर केमफर्टस प्राईवेट लिमिटेड

- (10) उपरोक्त प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों के अतिरिक्त जांच की कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों की ओर से भी कुछेक कानूनी निवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, निम्नलिखित पक्षकारों ने कोई आयातक/निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं:-

1.	भारत गणराज्य में रूस परिसंघ के व्यापारी प्रतिनिधि
2.	जेएससी एक्टिविबिन्सक क्रोमियम केमिकल्स प्लांट, कजाकिस्तान
3.	जेएससी एनपीसीसी, रूस
4.	स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	स्काईस्टेप ट्रेडिंग लिमिटेड
6.	कजाकिस्तान गणराज्य का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंत्रालय और प्रथम उप-मंत्री
7.	रूस परिसंघ का उद्योग और व्यापार मंत्रालय

- (11) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय वृत्तान्त सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध कराया था, जो कि हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुला रखा गया था।

- (12) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वह विगत तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने की व्यवस्था करें और प्राधिकारी

- को उनसे ऐसी सूचना प्राप्त हो गई थी। प्राधिकारी ने कारोबार की विधिवत् जांच करने के बाद आयातों की मात्रा का परिकलन और आवश्यक विश्लेषण करने के लिए और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (13) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उन्हें निर्मित करने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे “एनआईपी” कहा गया है) का आकलन किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटन-रोधी शुल्क, घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (14) प्राधिकारी द्वारा जितना आवश्यक समझा गया था, आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन करने के लिए तालिका का अध्ययन किया गया था। वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ जहां कहीं भी लागू होता है, वहां आवश्यक संशोधन सहित केवल सत्यापित सूचना पर विश्वास किया गया है।
- (15) आवेदक उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा जितना आवश्यक समझा गया था, तालिका अध्ययन किया गया था और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उस पर विश्वास किया गया।
- (16) वर्तमान पाटन-रोधी जांच के प्रयोजनार्थ यह जांच 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक (12 महीनों) की अवधि के लिए की गई थी। क्षति का विश्लेषण करने के परिप्रेक्ष्य में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच अवधि भी शामिल है।
- (17) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए 26 मार्च, 2018 को सार्वजनिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों का सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत कर दें। पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकट किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर लें और उन पर अपने प्रत्युत्तर तक प्रस्तुत कर दें।
- (18) हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए लिखित निवेदनों/प्रत्युत्तरों में दिए गए तर्कों पर वर्तमान जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- (19) इस जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का जहां कहीं भी प्रासंगिक पाया गया है, वहां प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में निदान किया गया है।
- (20) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।
- (21) रूस से डी-मिनिमस डंपिंग मार्जिन को ध्यान में रखते हुए, रूस के खिलाफ पाटन-रोधी जांच समाप्त कर दी गई है इसलिए, इस जांच के विषय वाले देश केवल दक्षिण अफ्रीका, कज़ाख़स्तान और तुर्की का गठन करते हैं।
- (22) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।
- (22) प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 67.95 रूपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु"**ख.1 घरेलू उद्योग के निवेदन**

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम डाईक्रोमेट है, जिसे एनहाइड्रस और डाई-हाइड्रेट के रूप में 'सोडियम डाईक्रोमेट' के नाम से भी जाना जाता है (जिसे आग "संबद्ध वस्तुएं" भी कहा गया है)। विचाराधीन उत्पाद का रासायनिक सूत्र "एनए2सीआर207" है। सोडियम डाईक्रोमेट डाई-हाइड्रेट रूप में और सोडियम डाईक्रोमेट एनहाइड्रस के रूप में उत्पाद के बीच अंतर केवल दोनों में आद्रता का निहित होना है।
- (2) सोडियम डाईक्रोमेट को कई ऑर्गेनिक सिंथेसिस और दवाओं, विशेषकर इबुप्रोफेन के उत्पादन के लिए आक्सीकारक एजेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे धातु परिष्करण उद्योगों, जंग रोधी उपयोगों, जल शोधन रसायनों, पिगमेंट और पेंट इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है। इसे अन्य क्रोमियम रसायनों के निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है।
- (3) याचिकादाता डाई-हाइड्रेट रूप में सोडियम डाईक्रोमेट उत्पादित करता है, लगभग जिसमें 11-12% तक आद्रता निहित होती है। दक्षिण अफ्रीका से आयात भी डाई-हाइड्रेट रूप में होते हैं, जबकि रूस, तुर्की और कजाकिस्तान से आयात न्यूनतम आद्रता युक्त एनहाइड्रस रूप में किए जाते हैं। इसलिए घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच उचित तुलना करने के लिए आद्रता को समानुपात रूप से समंजित किया गया है।
- (4) सोडियम डाईक्रोमेट डाई-हाइड्रेट रूप में और सोडियम डाईक्रोमेट एनहाइड्रस के रूप में उत्पाद के बीच अंतर केवल दोनों में आद्रता का निहित होना है। विचाराधीन उत्पाद को पहले विलेयन के रूप में उत्पादित किया जाता है, जिसमें डाईक्रोमेट की मात्रा 50% होती है। परिवहन लागत में बचत करने के लिए आद्रता को वाष्पित किया जाता है और कुछ उत्पादकों द्वारा उसे घटा कर 11-12% और अन्य उत्पादकों द्वारा 0.5% कर दिया जाता है। उत्पाद में जितनी भी आद्रता की मात्रा होती है, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त करने से पहले, उपभोक्ता के स्तर पर सबसे पहले संसंधान प्रक्रिया से उत्पाद को दुबारा 50% की सीमा में पतला करना होता है। चूंकि उपभोक्ता द्वारा उत्पाद का उपयोग उसमें विद्यमान डाईक्रोमेट की मात्रा के लिए किया जाता है और यदि डाईक्रोमेट अधिक होता है, तो उसका तात्पर्य यही है कि समानुपात रूप से उसकी कम खपत होगी।
- (5) सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता आवेदक द्वारा उत्पादित सोडियम डाईक्रोमेट का उपयोग कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद का उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं है और ये उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का उपयोग, एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।
- (6) विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के तहत सीमा शुल्क उप-शीर्ष 2841 3000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) उत्पाद के दोनों रूपों में अंतर है। जांच शुरू करने की अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद के दोनों रूपों के बीच अंतर होने का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। इन दोनों रूपों के उत्पाद की कीमत, विनिर्माण, भौतिक और रासायनिक गुण-क्षमताएं भिन्न हैं। उत्पाद के दोनों रूप भिन्न हैं और उन्हें एकल उत्पाद नहीं माना जा सकता है।

- (2) एससीपी का उत्पाद, विचाराधीन उत्पाद से भार, छवि, घुलनशीलता, विशिष्ट भार, विलेयन का ताप जैसी गुण-क्षमताओं से भिन्न है। एससीपी के उत्पाद में आद्रता की मात्रा 0.2% - 0.4% तक होती है और उसे आसानी से विचाराधीन उत्पाद से विशेष रूप से पहचाना जा सकता है। याचिकादाता का यह बयान असत्य है कि एससीपी के उत्पाद में आद्रता नगण्य है।
- (3) घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू कीमतों और आयातों के बीच समंजन का आधार प्रदान नहीं किया गया है अथवा प्रमाणित नहीं किया गया है।
- (4) घरेलू उद्योग ने रूस, तुर्की और कजाकिस्तान से आयातित विचाराधीन उत्पाद को यह बता कर गलत वर्गीकृत किया है कि उसमें 99% आद्रता निहित है। रूस, तुर्की और कजाकिस्तान से आयातित उत्पाद में लगभग 2 % आद्रता निहित है। सुरक्षा के परिणाम भी यह सिद्ध करते हैं कि हाईड्रेटिड किस्म के उत्पाद का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है, जिसमें 12-14% आद्रता निहित है तथा आयातित उत्पाद एनहाइड्रस के रूप में होते हैं और उनमें लगभग 2% आद्रता निहित है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तु के दायरे के बारे में विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट कर लिया है। विचाराधीन उत्पाद के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि -

- (1) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “सोडियम डाईक्रोमेट” है, जिसे एनहाइड्रस और डाई-हाइड्रेट के रूप में ‘सोडियम डाईक्रोमेट’ के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम डाईक्रोमेट को कई ऑर्गेनिक सिंथेसिस और दवाओं, विशेषकर इबुप्रोफेन के उत्पादन के लिए आक्सीकारक एजेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसे धातु परिष्करण उद्योगों, जंग रोधी उपयोगों, जल शोधन रसायनों, पिगमेंट और पेंट इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है। इसे अन्य क्रोमियम रसायनों के निर्माण में भी उपयोग में लाया जाता है।
- (2) हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि “सोडियम डाईक्रोमेट” एनहाइड्रस और डाई-हाइड्रेट रूपों में विभिन्न उत्पाद है, यह नोट किया जाता है कि एनहाइड्रस और डाई-हाइड्रेट रूप विचाराधीन उत्पाद के मात्र दो रूप हैं। इन दोनों के बीच केवल यही अंतर है कि सोडियम डाईक्रोमेट डाई-हाइड्रेट और सोडियम डाईक्रोमेट एनहाइड्रस रूपों के इन दोनों रूपों में आद्रता की मात्रा होती है। याचिकादाता सोडियम डाईक्रोमेट एनहाइड्रस का उत्पादन करता है, जिसमें आद्रता की मात्रा लगभग 11-12% होती है, जबकि रूस, कजाकिस्तान और तुर्की से आयातित एनहाइड्रस रूप के उत्पाद में आद्रता की मात्रा नगण्य होती है। तथापि, दक्षिण अफ्रीका से अयात डाई-हाइड्रस रूप में होता है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि इन दोनों रूपों के उत्पाद का अंत-प्रयोग, अनुप्रयोग और विनिर्माण प्रक्रिया भी समान होती है। उपभोक्ता एनहाइड्रस/डाई-हाइड्रेट दोनों रूपों की आयातित संबद्ध वस्तुओं और डाई-हाइड्रेट रूप में घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता और उपयोगों को देखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि सोडियम डाईक्रोमेट एनहाइड्रस और डाई-हाइड्रेट, विचाराधीन उत्पाद नामतः ‘सोडियम डाईक्रोमेट’ के दो रूप मात्र हैं।
- (3) इसके अतिरिक्त वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ और उचित तुलना के लिए एनहाइड्रस रूप में उत्पाद, जिसे कजाकिस्तान, रूस और तुर्की से निर्यात किया जाता है, में नगण्य आद्रता होने के कारण उसे ‘डाई-हाइड्रेट’ में परिवर्तित किया गया है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया जाता है, ताकि संबद्ध वस्तुओं की मात्रा और उसकी परिशुद्धता को समान स्तर पर लाया जा सके। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन करने के दौरान और उनके द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के डाई-हाइड्रेट रूप का कम भार होता है, जो कि लगभग 298 ग्राम/मोल. होता है, जबकि संबद्ध वस्तुओं का एनहाइड्रस रूप का मोलेक्यूलर भार लगभग 262 ग्राम/मोल. होता है। आद्रता की मात्रा के कारण इन दोनों भिन्न रूपों के विचाराधीन उत्पाद के मोलेक्यूलर भार को कजाकिस्तान, रूस और तुर्की से आयातित मात्रा को एनहाइड्रस से डाई-हाइड्रेट में परिवर्तित कर

दिया जाता है, ताकि उनकी घरेलू रूप से उत्पादित डाई-हाइड्रस सोडियम डाईक्रोमेट के साथ उचित तुलना की जा सके। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी इसकी संपुष्टि करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद सोडियम डाईक्रोमेट है। इसे सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के तहत सीमा-शुल्क उप शीर्ष 2841 3000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. घरेलू उद्योग और उसका आधार

ग. 1 घरेलू उद्योग के निवेदन

7. घरेलू उद्योग के दायरे और उसके आधार के संबंध में जांच की कार्यवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) आवेदन-पत्र मेसर्स विष्णु केमिकल्स लिमिटेड द्वारा अपने दो समर्थकों नामतः मेसर्स कनकदुर्गा केमिकल्स और मेसर्स कोणार्क क्रोमे केमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। समर्थकों के बिना और उनके साथ, याचिकादाता कंपनी का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख भाग बनता है।
- (2) याचिकादाता ने किसी भी संबद्ध देश से न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित है।
- (3) याचिकादाता का पर्याप्त आधार है और वह नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनता है।
- (4) उसके समर्थकों ने उत्पादन, विक्रियों, भंडार और क्षमता से संबंधित सूचना प्रदान की है। मेसर्स कनकदुर्गा केमिकल्स को निर्यातकों द्वारा प्रचण्ड पाटन किए जाने के कारण अपना संयंत्र बंद करना पड़ा था। याचिकादाता का कार्य-निष्पादन दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हो रही है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

8. घरेलू उद्योग और उसके आधार के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) अन्य समर्थकों द्वारा प्रदत्त सूचना वर्तमान जांच में अविश्वसनीय और असंबद्ध है। समर्थकों सहित किसी भी उत्पादक ने कोई सूचना प्रदान नहीं की है और इस प्रकार याचिकादाता द्वारा यह दर्शाने का एक प्रयास मात्र है कि अन्य भारतीय उत्पादक भी प्रभावित हैं।
- (2) मेसर्स कनकदुर्गा केमिकल्स के दावे की कोई मेरिट नहीं है क्योंकि इसने न तो जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं का कोई उत्पादन किया है और न ही यह बताया है कि वह दुबारा उत्पादन करना शुरू कर सकता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. समान वस्तु के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित प्रावधान इस प्रकार है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में लगे हुए हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

10. वर्तमान आवेदन-पत्र मेसर्स विष्णु केमिकल्स लिमिटेड द्वारा अपने दो समर्थकों नामतः मेसर्स कनकदुर्गा केमिकल्स और मेसर्स कोणार्क क्रोमे केमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का 82% बनता है। इसके अतिरिक्त आवेदक, संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं है और उसने स्वतः संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है। संबद्ध वस्तुओं को उत्पादक-वार उत्पादन के संबंध में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने बताया है कि विभाग “सोडियम डाईक्रोमेट” के उत्पादन के व्यौरो का अनुवीक्षण नहीं करता है।

11. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना की जांच के आधार पर यह पता चलता है कि अकेले घरेलू उद्योग का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का “प्रमुख भाग” बनता है। तदनुसार, कानूनी प्रावधानों और मामले के तथ्यों की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर पात्र घरेलू उद्योग बनता है और आवेदक उपरोक्त नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार आधार की आवश्यकता को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

12. जांच की कार्यवाही के दौरान गोपनीयता के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (1) याचिकादाता ने केवल ऐसी सूचना की गोपनीयता का दावा किया है, जिसकी गोपनीयता की अनुमति नियमावली के अंतर्गत दी गई है और जो कि प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार है।
 - (2) याचिकादाता ने आवेदन-पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त के पर्याप्त व्यौरे प्रदान किए हैं। कोई भी हितबद्ध पक्षकार सूचना के ऐसे किसी विशिष्ट अंश का उल्लेख नहीं कर पाया है, जिसकी गोपनीयता का दावा किया गया है और जिसकी गोपनीयता, पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार यथोचित नहीं है।
 - (3) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बीजक पश्चात डिसकाउन्ट्स से संबंधित सूचना का प्रकटन इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका स्रोत तृतीय पक्षकार है और प्रकटन से तृतीय पक्षकार के व्यवसाय के हित प्रभावित हो सकते हैं।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. जांच की कार्यवाही के दौरान अत्यधिक गोपनीयता के बारे में निर्यातकों/आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (1) गोपनीय सूचना के दावे की जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि सुरक्षा महानिदेशक ने अपने सुरक्षा जांच परिणाम में ऐसी सूचना का प्रकटन किया है, जिसकी गोपनीयता का दावा किया गया था।
 - (2) बीजक पश्चात नोट को गोपनीय माना गया है, जिसका प्रकटन मेसर्स लेनक्सेस को किया जाना चाहिए क्योंकि यह सीधे उनसे संबंधित है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 में उल्लिखित व्यवस्था निम्नानुसार है:-

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

15. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दिया था, जिसमें नियम 6 (7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय वृत्तान्त निहित था।

- (1) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रदान करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय वृत्तान्त सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध कराया था, जो कि हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुला रखा गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित सूचना की गोपनीयता का दावा किया है।

ड. विविध निवेदन

ड.1 घरेलू उद्योग के निवेदन

16. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) घरेलू उद्योग समंजन योजना को क्रियान्वित नहीं कर सका था क्योंकि सुरक्षा के अंतिम जांच परिणाम नकारात्मक थे और इस प्रकार घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होती रही। समंजन योजना को नहीं अपनाए जाने की संभावना के कारण घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट नहीं आई है।
- (2) पाटन-रोधी शुल्क का अनुरोध जन हित में नहीं है, बल्कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के बजाय उसको लागू नहीं करने से भारतीय उद्योग पर घातक प्रभाव पड़ते। ऐसी कम कीमत के निर्यातों के प्रभाव तब देखे गए थे, जब कजाकिस्तान को बाहर रखा गया था और उसे अपना व्यवसाय बंद करने के लिए बाध्य किया गया था।
- (3) पाटन-रोधी उपाय एक ऐसा उपाय है जो कि अनुचित व्यापार प्रथा के विरुद्ध लागू किया जाता है। राष्ट्रों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन यह पाटन/अनुचित व्यापार प्रथाओं की लागत पर नहीं किया जाना चाहिए।
- (4) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी संबद्ध कारकों पर विचार करने के बाद मात्रात्मक उत्पादन की स्वीकृति देता है और कोई भी व्यक्ति पाटन-रोधी जांच में उस पर आपत्ति नहीं उठा सकता है। सुरक्षा महानिदेशक को भ्रमित किया गया था और यह निर्णय देने में गलती की गई थी कि याचिकादाता के पास 70,000 मी.टन की उत्पादन क्षमता नहीं है।
- (5) घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों में आयातों के संदर्भ में जांच अवधि की सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 की अवधि में आयातों में गिरावट आई थी और इस प्रकार वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। जांच अवधि के दौरान आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी और इसका उल्लेख किया गया है। जांच अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट में उद्योग पर पाटन के प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है।
- (6) सुरक्षा महानिदेशक के परिणाम में आईबीआईएस के अनुसार आयातों पर विचार किया गया है, जबकि याचिकादाता ने आवेदन-पत्र में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विचार किया है। तथापि, सुरक्षा महानिदेशक के परिणाम में गलती से स्रोत के रूप में डीजीसीआईएंडएस का उल्लेख किया गया है।
- (7) याचिका में प्रदत्त याचिकादाता की क्षमता, संबद्ध उत्पाद की क्षमता है। संबद्ध उत्पाद का उत्पादन करने के लिए संयंत्र स्थापित किया गया था और घरेलू उपभोक्ताओं से आर्डर नहीं मिलने के कारण याचिकादाता संबद्ध उत्पाद के व्युत्पन्नों का उत्पादन करने के लिए विवश हुआ है।

- (8) वर्ष 2013-14 में पाटन-रोधी आवेदन-पत्र और सुरक्षा परिणाम में सूचना में अंतर होने के संबंध में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया था कि सुरक्षा प्राधिकारी द्वारा भिलाई संयंत्र की क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए उसकी क्षमता को 55600 मी.टन माना था, लेकिन पीसीबी आर्डर के अनुसार विजाग की क्षमता को सही ढंग से परिकलित नहीं किया गया था। तथापि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के आदेश के अनुसार जांच अवधि के दौरान इस जांच में विजाग संयंत्र की क्षमता को 70000 मी.टन माना गया है, जिसे प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित किया गया है। उसी अवधि के दौरान आयात की मात्रा की संख्याओं में अंतर होने के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया था कि सुरक्षा महानिदेशक ने डी जी सी आई एंड एस के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा को लिया है, लेकिन वर्तमान जांच में डी जी सी आई एंड एस के कारोबार-वार आयात के आंकड़ों पर विचार किया गया है और उन्हें विधिवत् सत्यापित किया गया है। इसी प्रकार सुरक्षा जांच में घरेलू बिक्रियां पर विशाखापटनम से लेकर विजाग तक केप्टिव अंतरण के रूप में विचार किया गया था, जबकि इस जांच में घरेलू बिक्रियों को केप्टिव खपत माना गया है। तथापि, सुरक्षा जांच में इस कारणवश कि विशाखापटनम से भिलाई संयंत्र तक अंत अंतरण को घरेलू बिक्रियां माना गया है, उनमें मामूली अंतर अभी भी विद्यमान है। तथापि, पाटन-रोधी जांच में उसे माल-सूची के रूप में माना गया है।
- (9) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि यदि सुरक्षा शुल्क लगाया जाता है, तो वह प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा। चूंकि सुरक्षा शुल्क नहीं लगाया गया है, इसलिए ऐसी आशा करना उपयुक्त नहीं है कि घरेलू उद्योग अभी भी समंजन योजना क्रियान्वित करेगा। तथापि, उसने बताया है कि समंजन योजना के क्रियान्वयन के कार्य की प्रक्रिया पहले से चल रही है। यहां तक कि घरेलू उद्योग सुरक्षा जांच में दी गई समंजन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रयास कर रहा है, फिर भी घरेलू उद्योग इसे पूरी तरह से क्रियान्वित करने में असमर्थ रहा है। समंजन योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में घरेलू उद्योग सीओ2 एसडिफिकेशन कारखाना की स्थापना करने में सक्षम रहा है और उसका प्रयोगिक प्रचालन शुरू किया जा रहा है। तथापि, सीओ2 रिकवरी कारखाना अभी स्थापित किया जाना है। समंजन योजना के अंतर्गत लागत को कम करने के उपाय के रूप में सीओ2 एडिफिकेशन और रिकवरी प्रक्रिया की पूरी स्थापना करने में कम से कम 2 वर्ष लग जाएंगे। तथापि, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि उसके संबंध में पाटन-रोधी शुल्क लगाने पर विचार किया जाए क्योंकि वे घरेलू उद्योग को किसी प्रकार की और क्षति पहुंचाए बिना समंजन योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं।

इ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

17. जांच की कार्रवाई के दौरान विविध मुद्दों के बारे में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) सुरक्षा जांच परिणाम में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए एक क्रियान्वयन योजना प्रस्तुत की गई थी। यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्या उसे क्रियान्वित किया गया है?
- (2) याचिकादाता द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, उसको हो रहे घाटों के उसके दावे का समर्थन नहीं करती है। उसी रिपोर्ट में प्रस्तावित विस्तार परियोजनाओं का उल्लेख भी है।
- (3) तुर्की और भारत के बीच बढ़ रही व्यापार मात्रा के बावजूद तुर्की के लिए व्यापार की कमी भी बढ़ रही है। तुर्की के निर्यातों की मात्रा भारतीय बाजार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है और कोई भी पाटन उपाय से तुर्की के लिए व्यापार की कमी में संभवतः और गिरावट लाएगा।
- (4) याचिकादाता उचित कीमत के उत्पादों पर अपने प्रभुत्व और एकाधिकार की स्थिति को बचाना चाहता है।
- (5) बीजक पश्चात छूट देने के दावे को कोई तथ्य परक आधार नहीं है। अपने दावे के समर्थन में याचिकादाता ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

- (6) मूल्य की गलत घोषणा किए जाने के कारण अधिक राशि का बीजक बनाने के दावे की जांच, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 3 और संबंधित प्रक्रियाओं अथवा विदेश विनमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है और न कि पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत।
- (7) बीजक पश्चात् छूट के दावे को एक मात्र आधार यह कि दक्षिण अफ्रीका से आयातित उत्पाद, घरेलू उद्योग के उत्पाद से उच्चतर है। ऐसे अनेक कारक हैं, जहां गुणवत्ता के महत्व और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद की आपूर्ति करने में असमर्थता आदि सहित कारणों से आयात किए जाने होते हैं। वास्तव में सुरक्षा महानिदेशक ने ऐसे मामलों को नोट किया है, जहां घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं को अपेक्षित मात्रा में और गुणवत्ता के सोडियम डाईक्रोमेट की आपूर्ति करने में असमर्थ रहा था।
- (8) याचिकादाता द्वारा बताई गई उत्पादन क्षमता गलत है क्योंकि उसमें याचिकादाताओं की कुल क्षमता शामिल है, जबकि उनके द्वारा अन्य उत्पाद भी उत्पादित किए जाते हैं। याचिकादाता केवल सीमित मात्रा में उत्पाद बेच सकता है। जैसा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहमति आदेश में देखा जा सकता है और उसमें उल्लिखित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए याचिकादाता वास्तव में उत्पाद की प्रति दिन लगभग 54 मी.टन उत्पादन कर सकता है। जांच अवधि के दौरान व्यापारिक बाजार में कुल घरेलू बिक्रियां 13,853 मी.टन थीं। इस प्रकार कुल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सोडियम डाईक्रोमेट की अपनी घरेलू बिक्रियां बढ़ाने के लिए कोई और गुंजाईश नहीं है। मात्रा के प्राचलों के बारे में याचिका में प्रदत्त सूचना तथा सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम में प्रकट की गई मात्रा संबंधी सूचना के बीच वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए अंतर है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. विविध मुद्दों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विविध निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) सुरक्षा जांच में प्रदान की गई समंजन योजना के क्रियान्वयन के मुद्दे के संबंध में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उसको निरंतर क्षति हुई है, लेकिन घरेलू उद्योग, सुरक्षा प्राधिकारी के समक्ष यथा-प्रस्तुत समंजन योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया कर रहा है। दिनांक 15 जनवरी, 2015 के सुरक्षा परिणाम में घरेलू उद्योग ने वैकल्पिक सीओ2 एसिडिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करके उत्पादन की लागत में कटौती करने के संबंध में समंजन योजना निर्धारित की थी। तथापि, घरेलू उद्योग ने सुरक्षा प्राधिकारी के समक्ष यह निवेदन किया है कि सुरक्षा शुल्क लगाने से उसके उत्पादन और क्षमता उपयोग में बढ़ोतरी होगी, जिसके फलस्वरूप ऊपरी लागत में कमी होगी जिसके परिणाम स्वरूप लागत में और अधिक गिरावट आएगी। सुरक्षा प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इन विचारों की जांच करने के बाद कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समंजन योजना को अपने सीओ 2 एसिडिफिकेशन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित किए बिना है, ताकि यह पता चल सके कि घरेलू उद्योग विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा को सुव्यवस्थित कर सकेगा। तथापि, सुरक्षा उपाय के लिए अपेक्षित कारणात्मक संबंध और अन्य कारक नहीं होने को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा जांच को समाप्त कर दिया गया था।
- (2) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया था कि वह एक वैकल्पिक सीओ2 एसिडिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करके लागत को कम करने पर ध्यान संकेन्द्रित करेगा और समंजन योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में घरेलू उद्योग सीओ2 एसिडिफिकेशन संयंत्र की स्थापना करने में सक्षम रहा है और प्रायोगिक प्रचालन शुरू किया जा रहा है। तथापि, सीओ2 रिकवरी संयंत्र अभी स्थापित किया जाना है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह भी निवेदन किया है कि समंजन योजना के अंतर्गत लागत को कम करने के उपाय के रूप में सीओ2 एसिडिफिकेशन और रिकवरी संयंत्र प्रक्रिया की पूरी स्थापना और स्थिरीकरण करने में कम से कम 2 वर्ष लग जाएंगे। यह नोट किया जाता है कि जैसा कि सुरक्षा परिणाम में सुझाव दिया गया है, कथित समंजन योजना घरेलू उद्योग को अत्यधिक लागत प्रभावी बना सकती थी। तथापि, घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को जैसा वह विद्यमान है, उस पर विचार करने और इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या सुरक्षा शुल्क जांच के विपरीत

क्षति अवधि के दौरान विशिष्ट स्रोतों से जो कि सभी स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयात बनते हैं, पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में कोई गिरावट आई है।

- (3) इस तर्क के संबंध में कि पाटन उपायों से तुर्की के साथ व्यापार में कमी में असंतुलन होने की संभावना है, यह नोट किया जाता है कि उचित और प्रतिस्पर्धी कीमत पर राष्ट्रों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है।
- (4) इस तर्क के संबंध में कि याचिकादाता एकाधिकार स्थापित करने और अपने बाजार की स्थिति के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है, यह नोट किया जाता है कि बाजार में अन्य उत्पादक हैं तथा उनमें से दो ऐसे उत्पादक हैं, जिन्होंने आवेदन-पत्र का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी उपाय यदि किया जाता है, तो रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना की पूरी जांच और विश्लेषण करने के बाद यह पता चलेगा कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। फिर भी पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे, बल्कि प्रयोक्ता के पास गैर-पाटित स्रोतों से उचित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के व्यापक विकल्प और स्वतंत्रता होगी, जिनसे बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा स्थापित होगी।
- (5) जैसा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा प्रमाणित घरेलू उद्योग के पास उत्पादन करने की क्षमता होने और घरेलू उद्योग द्वारा निचले स्तर के उत्पादों पर ध्यान संकेन्द्रित करने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वीकृत आदेश की जांच की है। मेसर्ज विष्णु केमिकल्स ने विजाग संयंत्र के लिए 70,000 मी.टन प्रति वर्ष (210 मी.टन प्रति दिवस) अपनी वास्तविक स्थापित क्षमता होने का दावा किया है। इसके अतिरिक्त भिलाई संयंत्र (छत्तीसगढ़) में 16,000 मी.टन की उसकी अतिरिक्त क्षमता भी स्थापित थी। लेकिन घरेलू उद्योग ने सूचित किया है कि वर्ष 2015-16 से भिलाई संयंत्र में कोई उत्पादन नहीं हुआ था। यह नोट किया जाता है कि आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 23.04.2012 के अपने आदेश संख्या 7301/पीसीबी/जेडओ-वीएसपी/टेक/2012-58 द्वारा मेसर्ज विष्णु केमिकल्स को केवल @120 एमटीपीडी सोडियम डाईक्रोमेट का उत्पादन करने की स्वीकृति प्रदान की थी। एक वर्ष में 333 कार्य दिवस मानते हुए सोडियम डाईक्रोमेट के लिए क्षमता प्रति वर्ष 39960 मी.टन बनती है। एपीपीसीबी ने दिनांक 20.06.2016 के स्वीकृति आदेश द्वारा सोडियम डाईक्रोमेट की प्रति दिन की क्षमता में संशोधन कर उसे 210 मी.टन कर दिया था। उपरोक्त के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 20.06.2016 से सोडियम डाईक्रोमेट की बढ़ी हुई क्षमता पर विचार किया है और यह जांच अवधि के दौरान 63,360 मी.टन बनती है।
- (6) इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने यह भी निवेदन किया है कि भिलाई जिसकी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता 16,000 मी.टन थी, में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन, वर्ष 2015-16 से बंद कर दिया गया था, जिसका कारण घरेलू बाजार के हिस्से को संबद्ध वस्तुओं के आयातों द्वारा हथियाए जाने से घरेलू बाजार का उपलब्ध नहीं होना था। इस प्रकार हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क की कोई मेरिट नहीं है कि सोडियम डाईक्रोमेट के माल की बिक्रियों की क्षमता में कमी होने से अथवा घरेलू उद्योग द्वारा निचले स्तर के बाजार पर ध्यान संकेन्द्रित करने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त फिर भी यह मानते हुए कि माल की बिक्रियों के लिए घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता प्रचलित मांग से कम है, यह नोट किया जाता है कि मांग और पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर से संबद्ध वस्तुओं का पाटन उचित सिद्ध नहीं हो जाता है। आयातों को उचित कीमतों पर बनाए जाने की आवश्यकता है।
- (7) बिक्रियों, केप्टिव क्षमता और उत्पादन आदि के आंकड़ों में अंतर होने के तर्क के संबंध में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि सुरक्षा प्राधिकारी को भी वर्ष 2013-14 के लिए यही सूचना प्रदान की गई थी, जिसे इस जांच में प्रस्तुत किया गया है। इसके समर्थन में घरेलू उद्योग ने इस अवधि के लिए लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर यह नोट किया जाता है कि लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार बिक्रियों और केप्टिव खपत के संयुक्त आंकड़े, सुरक्षा जांच परिणाम में प्रकट किए गए बिक्रियों और केप्टिव खपत के संयुक्त आंकड़ों के समानु रूप हैं। तथापि, सुरक्षा जांच परिणाम में प्रकट किए गए बिक्रियों और केप्टिव खपत के पृथक आंकड़े, घरेलू उद्योग की लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में सूचित आंकड़ों से भिन्न हैं। ऐसे अंतर के संबंध में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि सुरक्षा जांच में घरेलू बिक्रियों को विशाखापटनम से भिलाई संयंत्र को केप्टिव अंतरण के रूप में माना गया था, जबकि इस जांच में घरेलू बिक्रियों को केप्टिव बिक्रियों के समान माना गया है। तथापि, इस कारणवश उसमें मामूली अंतर अभी भी है कि विशाखापटनम से भिलाई को अंतः शेष अंतरण को सुरक्षा जांच में घरेलू बिक्रियां माना

गया है, लेकिन पाटन-रोधी जांच में उसे माल-सूची के रूप में माना गया है, जैसा कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है। इसी प्रकार यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने सुरक्षा प्राधिकारी के समक्ष वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए अन्य उत्पादकों की विक्रियों को 8,500 मी.टन सूचित किया है, लेकिन सुरक्षा प्राधिकारी ने अन्य भारतीय उत्पादकों की मात्रा 6,850 मी.टन सूचित की है, जिसके फलस्वरूप समान अवधि के लिए मांग के परिकलन में अंतर है। तथापि, प्राधिकारी ने इस पाटन-रोधी जांच में पाटन और क्षति दोनों का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ पहले से उपलब्ध जानकारी को माना है।

- (8) सुरक्षा परिणाम में तथा वर्तमान जांच में डीजीएडी को प्रस्तुत याचिका में यथा सूचित वर्ष 2013-14 के लिए आयात के आंकड़ों में अंतर होने के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि सुरक्षा परिणाम में इस प्रकार से प्रयुक्त आंकड़े, डी जी सी आई एंड एस के प्रकाशित आंकड़े थे, जबकि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त आंकड़े, डी जी सी आई एंड एस के कारोबार-वार आयात आंकड़े थे। चूंकि वर्तमान याचिका और सुरक्षा परिणाम में बताए गए आंकड़ों के स्रोत भिन्न हैं, इनके आंकड़ों में भी मामूली अंतर है। इस जांच में प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की जांच करने के प्रयोजनार्थ जांच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

19. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (1) (ग) के अंतर्गत "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है :

(1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(2) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप- धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च.1 घरेलू उद्योग के निवेदन

20. वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) सामान्य मूल्य का तात्पर्य दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, तुर्की और रूस के घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की कीमत से है। याचिकादाता द्वारा संबद्ध देशों के घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की कीमत की सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, याचिकादाता संबद्ध देशों के घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की कीमत की कोई सूचना/साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया है।

- (2) याचिकादाता ने संबद्ध देशों में उत्पादन की लागत के बेहतर अनुमानों के आधार पर और डी जी सी आई एंड एस के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार प्रमुख कच्चे माल की कीमतों और संबंधित देश में यथा प्रचलित विद्युत की कीमतों को ध्यान में रख कर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
- (3) किसी भी प्रतिवादी निर्यातक ने अपने उत्तर में ऐसा कोई सार्वजनिक दावा नहीं किया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम है। इसका तात्पर्य यह है कि इन विदेशी उत्पादकों ने अपनाए गए अनुचित पाटन को मौन रूप से स्वीकार कर लिया है।
- (4) याचिकादाता ने भारत में संबद्ध आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस और द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (5) प्राधिकारी को पाटन मार्जिन निर्धारित करना चाहिए और उसके परिणाम स्वरूप भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना, विशिष्ट पृथक कीमत के साथ करके कीमत में कटौती होने और क्षति मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए क्योंकि निर्यात कीमत में विभिन्न क्रेताओं और समय-अवधि के अनुसार अत्यधिक अंतर व्याप्त है, जैसा कि आयात विवरण से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी कारोबार में जहां पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन नकारात्मक है, वहां उन्हें ऐसे निर्धारण के प्रयोजनार्थ अपवर्जित किए जाने की आवश्यकता है।
- (6) याचिकादाता वास्तविक साक्ष्य से संबंधित नहीं हैं और इसलिए ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि वे सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए उसे प्रस्तुत करेंगे। याचिकादाताओं ने बेहतर उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के लिए सूचना प्रदान की है।

च. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

21. प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:-

- (1) मेसर्ज सोडा सानयाई ए.एस., तुर्की के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में निर्यातक ने निवेदन किया है कि सामान्य मूल्य का परिकलन, तृतीय देश को लागत अथवा निर्यातों के आधार पर किया जाना चाहिए और न कि घरेलू बिक्रियों के आधार पर। कंपनी ने निवेदन किया है कि गृह बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियां, सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ भारत को उसकी निर्यातक कीमत से तुलनीय नहीं हैं। गृह बाजार एक विशिष्ट बाजार है और वितरकों/थोक विक्रेताओं को बिक्रियां, भारतीय अंत-प्रयोक्ताओं को बिक्रियों और गृह बाजार में संबद्ध माल के अंत प्रयोग, भारत में अंत प्रयोग से भिन्न हैं। भारतीय उपभोक्ता अधिकतर सेकेराइन के उत्पादक हैं, जबकि तुर्की में कोई भी सेकेराइन उत्पादक नहीं है। गृह बाजार में उपभोक्ता अधिकतर पेंट में प्रयुक्त करने के लिए संबद्ध वस्तु को खरीदते हैं, जो कि लकड़ी को क्षय होने से बचाता है। इस को ध्यान में रखते हुए मेसर्ज सोडा सानयाई ए.एस. ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ तृतीय देश की लागत अथवा कीमत पर विचार करें।
- (2) मेसर्ज सोडा सानयाई ए.एस., एक संबंधित व्यापारी, नामतः मेसर्ज सिसेकेम डिस टिकारेट ए.एस. ("एसडीटी") के माध्यम से निर्यात करती है। यह व्यापारी कंपनी वस्तुओं को भारत में उसी कीमत पर निर्यात करती है, जिस कीमत पर मेसर्ज सोडा सानयाई ए.एस. निर्यात करती है और इस व्यापारी कंपनी को मूल्य के निर्धारित प्रतिशत पर कमीशन अदा किया जाता है।
- (3) याचिकादाता ने बताया है कि संबद्ध देशों से निर्यात कीमत, उपभोक्ता आर समय-अवधि के अनुसार अत्यधिक भिन्न है, लेकिन यह प्रतिबिंबित नहीं करती है कि कैसे और कब कीमतों में अंतर होता है। प्रमाण नहीं होने के कारण भारित औसत सामान्य मूल्य की विशिष्ट पृथक निर्यात कीमत कार्य-प्रणाली के साथ तुलना को खारिज किया जाए और यह अनेक कारणों से गलत है। जैसा कि याचिकादाता द्वारा दावा किया गया है, मेसर्ज जेरोंग की कार्य-प्रणाली असंगत है और यह पाटन-रोधी नियमावली का उल्लंघन है।

- (4) चूंकि तुर्की और दक्षिण अफ्रीका से निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उनके लिए सामान्य मूल्य का परिकलन, उनके निवेदनों के आधार पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नावली के उत्तर में पृथक रूप से न्यूनतम पाटन मार्जिन का दावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (5) चूंकि तुर्की और दक्षिण अफ्रीका से निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उनके लिए निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण, उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. धारा 9 (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है:-

- (1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (2) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

23. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं और उन्हें सलाह दी थी कि वे निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से सूचना प्रदान करें। तथापि, निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को छोड़ कर, संबद्ध देशों से किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करके, इस जांच में कोई सहयोग नहीं दिया है:-

- (1) मेसर्ज लेनकेस सिसा प्राईवट लिमिटेड (उत्पादक), दक्षिण अफ्रीका
- (2) मेसर्ज लेनकेस (प्राईवट) लिमिटेड (निर्यातक), दक्षिण अफ्रीका
- (3) मेसर्ज सोडा सानयाई ए.एस. (उत्पादक), तुर्की
- (4) मेसर्ज सिसेकेम डिस टिकारेट ए.एस., तुर्की

24. चूंकि उपरोक्त उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, इसलिए प्राधिकारी का इन कंपनियों के संबंध में विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इन निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सामान्य कार्य-प्रणाली में पहले यह जांच करना शामिल है कि क्या प्रतिवादी निर्यातकों के अपने गृह बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्रियां, घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देने के लिए प्रतिनिधिक और अर्थक्षम हैं और क्या व्यापार की सामान्य प्रक्रिया की जांच, प्रतिवादियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार संतोषजनक थी।

25. संबद्ध देशों में असहयोगी निर्यातकों के मामले में प्राधिकारी का करार के अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

(क) सामान्य मूल्य**I. दक्षिण अफ्रीका****(क) मेसर्स लेनकेस सिसा प्राईवट लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका के लिए सामान्य मूल्य**

26. उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं को बेचा है, जो कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने पर विचार करने के लिए प्रतिनिधिक नहीं है। यहां तक कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए तृतीय देश के निर्यात पर विचार करने का अनुरोध नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने संबद्ध वस्तुओं के 30% निर्यात की बिक्री सूचना प्रदान की है। चूंकि उन्होंने तृतीय देश के सभी निर्यातों की संपूर्ण सूचना प्रदान नहीं की है और प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार लगभग सभी निर्यात घाटे पर किए गए हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में इन निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने एसजीए और उचित लाभ सहित उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। तदनुसार, निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

(ख) दक्षिण अफ्रीका से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

II. तुर्की**(क) मेसर्स सोडा सानयाई ए.एस., तुर्की के लिए सामान्य मूल्य**

28. उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच की गई थी। निर्यातक ने निवेदन किया है कि घरेलू बाजार विशिष्ट है और प्रचलित घरेलू बिक्रियों की कीमतें, भारत में निर्यात कीमत से तुलनीय नहीं हैं तथा संबद्ध उत्पाद के अंत प्रयोग के कारण ये अत्यधिक बढ़ाई गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप निर्यातक ने निवेदन किया है कि परिशिष्ट 1 में सूचित घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन नहीं किया जाए तथा इनका परिकलन लागत के आधार पर अथवा तृतीय देशों की निर्यात बिक्रियों के आधार पर किया जाए।

29. प्राधिकारी ने घरेलू बिक्री की जांच की और नोट किया कि घरेलू बाजार में बिक्री व्यापार की सामान्य अवधि में की गई हैं। इस तर्क में कोई जान नहीं है तथा यह दर्शाने के लिए साक्ष्य देने में भी विफल रहे कि घरेलू बाजार में कीमत पर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण निर्यातक की घरेलू बिक्री के आधार पर करने का निर्णय लिया। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि बनाई। यदि लाभप्रद लेनदेन 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देनों पर विचार करते हैं और जिन मामलों में लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हैं, उनमें केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है। इस मामले में व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी घरेलू बिक्रियों को लिया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्री 80 प्रतिशत से अधिक थीं। अतः निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा और ऋण लागत पर समायोजन का दावा किया है जिसे सत्यापित किया गया है और उसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ख) तुर्की में अन्य उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तुर्की के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। तुर्की ने सभी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन के रूप में उपलब्ध तथ्यों के रूप में निर्धारित किया है।

III. कजाखिस्तान**कजाकिस्तान में उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य**

31. कजाकिस्तान के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया। अतः प्राधिकारी ने उन्हें असहयोगी माना। कजाकिस्तान के उत्पादकों/निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने में सक्षम नहीं हैं तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के सिद्धांतों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। निर्यातकों के असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया। तदनुसार, सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन के रूप में निर्धारित किया गया है।

IV. रूस

32. रूस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया। अतः प्राधिकारी ने उन्हें असहयोगी माना। रूस के उत्पादकों/निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने में सक्षम नहीं हैं तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के सिद्धांतों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। निर्यातकों के असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया। तदनुसार, सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ख) निर्यात कीमत का निर्धारण**i. दक्षिण अफ्रीका****क) मैसर्स लैंक्सस (पीटीवाई) लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका के साथ मैसर्स लैंक्सस सीसा प्रा. लि. के लिए निर्यात कीमत**

33. मैसर्स लैंक्सस (पीटीवाई) लिमिटेड ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं और जांच की अवधि के दौरान उन्होंने भारत में 5553 मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उन्होंने परिशिष्ट-2 में कारखानागत से बाहर किसी समायोजन की सूचना नहीं दी, तथापि, माह-वार समायोजन सूचित किए गए हैं और परिशिष्ट-3क में दावा किया गया है। मैसर्स लैंक्सस (पीटीवाई) लिमिटेड ने पैकिंग, अंतर्देशीय भाड़ा, कार्गो देय, समुद्री भाड़ा और समुद्री बीमा के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। उचित सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन के रूप में कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित की है।

ख) दक्षिण अफ्रीका के असहयोगी उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि, दक्षिण अफ्रीका से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया है, अतः दक्षिण अफ्रीका में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन के रूप में निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

ii. तुर्की**क) सीसाकम डिस टिकारेट ए. एस., तुर्की के साथ मैसर्स सोडा सनायी ए. एस. के लिए निर्यात कीमत**

35. मैसर्स सोडा सनायी ए. एस. ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं और जांच की अवधि के दौरान उन्होंने भारत में 3240 मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उन्होंने भारतीय निर्यातक को अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, स्थानीय व्यय, समुद्री बीमा, ऋण लागत, बैंक प्रभार, विदेशी मुद्रा लाभ और कमीशन के निमित्त खर्चों का दावा किया है। विदेशी मुद्रा लाभ को छोड़कर उचित सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दी गई है क्योंकि वह सिद्ध नहीं था। तदनुसार, प्राधिकारी ने *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन के रूप में कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित की है।

ख) तुर्की के असहयोगी उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि, तुर्की से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया है, अतः तुर्की में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन के रूप में निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

iii. रूस

रूस में उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है, अतः रूस में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन के रूप में निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

iv. कजाकिस्तान

कजाकिस्तान में उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

38. कजाकिस्तान के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया। अतः प्राधिकारी ने उन्हें असहयोगी माना। कजाकिस्तान के उत्पादकों/निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन के रूप में निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

ग) पाटन मार्जिन तालिका

39. संबंधित संबद्ध देशों से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार निर्धारित किया गया है:

क्रम सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य - अमेरिकी डॉलर/मी. टन	निर्यात कीमत - अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन - अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन - %	पाटन मार्जिन रेंज - %
1.	दक्षिण अफ्रीका	मैसर्स लेंक्सेस सीसा प्रा. लि.	मैसर्स लेंक्सेस सीसा प्रा. लि.	***	***	***	***	15-20
2.	दक्षिण अफ्रीका	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	20-25
3.	तुर्की	मैसर्स सोडा सनाई ए. एस.	मैसर्स सीसेकम डिस टिकारेट ए. एस.	***	***	***	***	70-75
4.	तुर्की	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	80-85
5.	रूस	सभी	सभी	***	***	***	***	0-(5)
6.	कजाकिस्तान	सभी	सभी	***	***	***	***	20-25

छ. क्षति मूल्यांकन तथा क्षति की जांच एवं कारणात्मक संपर्क की पद्धति

I. क्षति जांच

ज.। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

40. वर्तमान जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षति से संबंधित अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- एक से अधिक देश से निर्यातक संबद्ध सामानों का निर्यात कर रहे हैं और इसीलिए नियमानुसार वर्तमान मामला संचयी मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है। पाटन मार्जिन और निर्यात की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है। संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए गए समान उत्पादों से सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

- ii. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग पूरी क्षति की अवधि में बढ़ी है। आयातों का भारतीय मांग का बहुत बड़ा हिस्सा है। आयातों में आधार वर्ष से 2015-16 तक गिरावट आई, परंतु जांच की अवधि में उनमें वृद्धि हुई और आधार वर्ष के स्तरों से ऊपर रहे जो आधार वर्ष से 24 प्रतिशत की वृद्धि और पूर्व वर्ष से 57 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।
- iii. संबद्ध देशों से आयात देश में कुल आयात का 98 प्रतिशत है। कुल आयातों और कुल माल से संबंधित आंकड़े इस कारण भिन्न हैं कि महानिदेशक, सुरक्षा ने आईबीआईएस के आंकड़ों का प्रयोग किया जबकि याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े दिए थे। उत्पादन की तुलना में आयातों में 2015-16 तक गिरावट आई, परंतु जांच की अवधि में उनमें उछाल आया। मांग की तुलना में संबद्ध आयातों ने वही प्रवृत्ति अपनाई और आधार वर्ष की तुलना में लगभग वही स्तर बनाए रखे।
- iv. पाटित आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। संबद्ध देशों से कीमत कटौती का स्तर जांच की अवधि में काफी बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप आयातों में काफी वृद्धि हुई। कीमत कटौती केवल उन आयात लेन-देनों पर विचार करते हुए निर्धारित की जानी चाहिए जिनकी आयात की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।
- v. उत्पादन लागत में आधार वर्ष से 2015-16 तक गिरावट आई, परंतु जांच की अवधि में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत ने भी वही प्रवृत्ति अपनाई, परंतु कीमतों में गिरावट, लागतों में गिरावट से अधिक थी; जांच की अवधि में जबकि लागतें बढ़ीं, बिक्री कीमत में गिरावट आई; बिक्री कीमत जांच की अवधि में उत्पादन की लागत से कम थी; आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम रही और इसीलिए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण एवं ह्रास हो रहा था।
- vi. याचिकाकर्ता की उत्पाद के लिए 70,000 मी. टन की क्षमता है। तथापि, पाटन के मद्देनजर याचिकाकर्ता को धुलाई में संयंत्र बंद करना पड़ा था जिसमें कि 16,000 मी. टन की क्षमता थी। वर्ष 2013-14 में न्यूनतम उत्पादन था और उसके बाद वह प्रचालनात्मक नहीं थी, अतः धुलाई में संयंत्र की क्षमता क्षति संबंधी सूचना में शामिल नहीं की गई है। उसको शामिल करने पर उत्पादन, बिक्री और उपयोग में भारी गिरावट दर्शाएगी।
- vii. घरेलू उद्योग का उत्पादन वर्ष 2015-16 तक बढ़ा, परंतु उसके बाद उस स्तर से नीचे के स्तर तक जांच की अवधि में गिरावट आई जो 2014-15 में और पूर्व वर्ष में प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता का क्षमता उपयोग तथा घरेलू बिक्री भी वही प्रवृत्ति दर्शाती है। कैप्टिव को शामिल करके और हटाकर घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों की कैप्टिव में वृद्धि हुई है। भारतीय मांग को पूरा करने की काफी क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा खोता रहा है।
- viii. कीमत संबंधी मानदंडों के संदर्भ में निष्पादन में गिरावट आई है। लाभ 2016 तक कम रहे। आयात कीमतों में गिरावट से घरेलू उद्योग बिक्री लागत से कम कीमत पर बिक्री करने को मजबूर था। कर पूर्व लाभ तथा निवेश पर आय में पूरी क्षति की अवधि में गिरावट आई।
- ix. मालसूची 2015-16 तक बढ़ी, परंतु जांच की अवधि में कम हुई क्योंकि घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए अपनी कीमतें कम कर दीं। इसके बावजूद, मालसूची का स्तर 2013-14 और 2015-16 के स्तर से ऊपर के स्तरों पर रुक गया।
- x. रोजगार और मजदूरी क्षति की अवधि में बढ़ी है। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई मजदूरी भी बढ़ी है, परंतु यह देश में मजदूरी कानूनों के अनुसार है और वह पाटन का प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाता। घरेलू उद्योग की उत्पादकता 2015-16 तक बढ़ी, परंतु उसके बाद कम हुई।
- xi. घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि भी प्रतिकूल रही है। मांग की मौजूदगी तथा उस मांग को पूरा करने की क्षमता के बावजूद घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उसे पूरा करने में सक्षम नहीं रहा है।
- xii. लाभप्रदता में वृद्धि नकारात्मक थी और घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हो रही हैं। बिक्री एवं उत्पादन में सुधार लाने के प्रयास किए गए और बिक्रियां बिक्री लागत के स्तरों से काफी कम स्तर की कीमत पर की गईं। फिर भी, मात्रात्मक मानदंड नहीं बढ़ पाए। घरेलू उद्योग के कार्यों की वर्तमान सूची से नए निवेश की अनुमति नहीं होती।

- xiii. संबंधित उत्पाद पर जोर था और अब भी है, परंतु याचिकाकर्ता बने रहने के लिए ही संबद्ध सामानों का निर्यात करने के लिए मजबूर था। घरेलू उद्योग में निचले उत्पादों के लिए क्षमता का उपयोग करने के बाद भी काफी क्षमताएं उपयोग करने के लिए थीं।
- xiv. मात्रा एवं मूल्य के संदर्भ में कैप्टिव खपत संबंधी सूचना घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए दी गई है।
- xv. संबद्ध आयातों में 2013-14 से 2015-16 तक गिरावट आई, घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई। जब जांच की अवधि में संबद्ध सामानों के आयात में वृद्धि हुई तो घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई। आयातों में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच में अवधि में 57 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग की बिक्री में 23 प्रतिशत तक गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप बाजार हिस्से में 26 प्रतिशत तक गिरावट आई।
- xvi. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में गिरावट पूर्णतः अवास्तविक हैं क्योंकि वे वर्तमान जांच के लिए क्षति का आधार नहीं हैं और दिए गए आंकड़े कम कीमत के आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आधार पर हैं।
- xvii. याचिकाकर्ता वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर आयातित अयस्क का प्रयोग कर रहा है तथा ओडिशा खनन निगम से अयस्क का उत्पादन कर रहा है और अयस्क के एक स्रोत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। क्रोम अयस्क की कीमतों में वृद्धि विश्व भर में सभी उत्पादकों के लिए अच्छी है और घरेलू उद्योग के लिए केवल एक संगत कारक नहीं है।
- xviii. वर्तमान मामला एक वह स्पष्ट स्थिति है जहां निर्यातक काफी दर पर देश में पाटन कर रहा है और "व्यापार की साधारण अवधि" संबंधी तर्क के साथ किए जा रहे पाटन को लेने प्रयास कर रहा है क्योंकि किसी भी स्थिति में अन्यथा मौजूदगी सिद्ध नहीं होती।
- xix. आयात उच्च स्तर पर थे और 2013-14 में भी उच्च स्तर पर थे जिसके कारण कनकदुर्ग 2014 में अपना उत्पादन बंद करने के लिए मजबूर था।
- xx. सुरक्षा संबंधी याचिका वर्तमान जांचों में शुल्क न लगाए जाने के लिए एक निर्धारण नहीं हो सकता क्योंकि मानी गई अवधि भिन्न है। क्षति मूल्यांकन "जैसी स्थिति है" के आधार पर और वर्तमान आंकड़ों के आधार पर तथा निश्चित रूप से पूर्व क्षति अवधि के आंकड़ों के आधार पर किया जाना है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी और सुरक्षा संबंधी कानून की स्कीम और क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं।
- xxi. याचिकाकर्ता पाटित आयातों के कारण अनुकूल घरेलू बाजार के अभाव में उत्पादन की कैप्टिव रूप से खपत करने के लिए मजबूर रहा है। आयातों की उच्च मात्रा के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई और कम रहा। घरेलू बिक्री 2015-16 तक वृद्धि के बाद जांच की अवधि में कम हुई। निर्यात और कैप्टिव खपत के बाद भी घरेलू उद्योग में क्षमता अनुपयुक्त रही।
- xxii. घटती हुई बिक्री और विमुद्रीकरण के बीच कोई सह संबंध नहीं है। क्षति आयात कीमतों में गिरावट से जांच की अवधि में आयात में वृद्धि के कारण है, जबकि लागत में वृद्धि हुई।
- xxiii. शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं है। सुरक्षा जांच के संबंध में किया गया संदर्भ सही नहीं है। सुरक्षा संबंधी कानून के असमान पाटनरोधी कानून सभी आयातों पर शुल्क नहीं लगाता। उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना अपाटित स्रोतों से संबद्ध सामानों को लेने में सक्षम होंगे। फिर भी, यद्यपि याचिकाकर्ता एक प्रमुख उत्पादक है, तथापि, उसे अपाटित स्रोतों से आने वाले संबद्ध सामानों से प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी और इसीलिए उसकी स्थिति को गलत नहीं बता सकता।
- xxiv. अन्य ज्ञात कारकों, यथा – निर्यात निष्पादन, प्रौद्योगिकी, देश के अन्य उत्पादकों का निष्पादन, पाटनरोधी करार में अथवा नियमावली में सूचीबद्ध व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
- xxv. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत न्यूनीकरण/ह्रास से घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानियां हुई हैं। काफी वित्तीय हानियों से नियोजित पूंजी पर आय तथा नकद लाभ में ह्रास हुआ है।
- xxvi. संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा काफी अच्छे स्तर पर रहा। घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा के दृष्टतम स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाया।

ज.II अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

4.1. वर्तमान जांच की अवधि में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति संबंधी निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. कैप्टिव खपत और उपलब्ध वास्तविक क्षमता के संबंध में याचिकाकर्ता के आंकड़ों का सत्यापन किया गया है। कैप्टिव खपत सहित मांग के वास्तविक आंकड़े प्रकट किए जाने चाहिए।
- ii. घरेलू उद्योग ने महानिदेशक सुरक्षा के परिणामों में आंकड़ों में अंतर तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन से संबंधित याचिका में उल्लिखित आंकड़ों, घरेलू उद्योग की बिक्री, अन्य उत्पादकों की बिक्री और अधिक महत्वपूर्ण घरेलू उद्योग के लाभ से संबंधित आंकड़ों में अंतर के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
- iii. जहां घरेलू उद्योग को आयातों में कीमत की अधिक कटौती अनुभव हुई है, वहां आयातों को हटाने की अनुमति नहीं है और वह पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.2 के अनुरूप नहीं है। कीमत कटौती क्षति निर्धारण में एकमात्र निर्धारक नहीं है। इसमें घरेलू उद्योग को क्षति का समग्र मूल्यांकन एक भाग बनता है और ऐसे किया जाता है ताकि जांचकर्ता अधिकारियों को क्षति एवं कारणात्मकता के मूल्यांकन के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।
- iv. घरेलू उद्योग के दावों के संबंध में वे लेन-देन हटाना क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए क्षति कारक नहीं है। यह निर्दिष्ट प्राधिकारी की एक सतत परिपाटी है कि वे किसी देश से सभी आयात लेन-देनों पर क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए ध्यान दें। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि इस परिपाटी को डब्ल्यूटीओ में चुनौती नहीं दी गई है और इसीलिए अपनाए जाने चाहिए। पाटनरोधी शुल्क क्षति मार्जिन पर लगाया जा सकता है, यदि वह पाटन मार्जिन से कम हो। यदि घरेलू उद्योग का दावा स्वीकार किया जाता है तो इसका यह अभिप्राय होगा कि ऐसे मामले नहीं हो सकते जहां क्षति मार्जिन नकारात्मक है और इसके परिणामस्वरूप नकारात्मक क्षति वाला कोई मामला नहीं होगा तथा कोई भी जांच रद्द नहीं होगी।
- v. मांग में वृद्धि के कारण आयातों में वृद्धि हुई है, फिर भी उससे बाजार हिस्से में ध्यान देने योग्य वृद्धि नहीं हुई। यह कहा जा सकता है कि आयातों में "काफी" वृद्धि हुई है।
- vi. लाभ एवं पाटित आयातों में गिरावट के बीच कोई संबंध नहीं है। आयातों से घरेलू उद्योग की बिक्री पर आघात नहीं हुआ है, इसके बजाए घरेलू उद्योग की बिक्री बढ़ी है।
- vii. कीमत कटौती तथा हुए लाभ/हानि के बीच कोई संबंध नहीं है। जब आयात कीमत कटौती कर रहे थे, तब भी घरेलू उद्योग लाभ कमा रहा था। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भी बढ़ा, तथापि, मुद्रा का अवमूल्यन क्षति का प्रमुख कारण है। क्रोम अयस्क की अस्थिरत कीमतें भी क्षति का कारण हैं।
- viii. कजाकिस्तान से आयातों का संचयी मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कजाकिस्तान से आयात घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए गए उत्पाद से भिन्न है।
- ix. उत्पादन, क्षमता, उपयोग, उत्पादन में कुल हिस्सा तथा कुल भारतीय उत्पादन में भी वृद्धि हुई। उत्पादन स्तर मांग के स्तर से अधिक थे। बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- x. कम हुई लाभप्रदता के दावे के बावजूद रोजगार और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है जो स्पष्ट रूप से कुप्रबंधन दर्शाता है।
- xi. याचिकाकर्ताओं का बाजार हिस्सा बढ़ा है। क्षमता एवं रोजगार में पूर्वानुमानित वृद्धि के कारण आरओआई में गिरावट आई।
- xii. उत्पादकता की सूची में 2012-13 में 100 से बढ़कर 2015-16 में 164 और 2016-17 में 138 तक की वृद्धि हुई। स्टॉक के लिए सूचीबद्ध आंकड़ों में 2013-14 में 100 से घटकर 2016-17 में 86 तक की गिरावट आई और इसीलिए यह कोई क्षति नहीं दर्शाता। कंपनी के निर्यात में गिरावट आई जो क्षति का वास्तविक कारण है और इसे आयातों के कारण नहीं होना चाहिए।
- xiii. कनकदुर्ग की ओर से यह अनुरोध किया गया था कि वह संबद्ध आयातों में वृद्धि के कारण 2014 में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर था। तथापि, 2013-14 और 2014-15 के बीच विचाराधीन उत्पाद के आयात वास्तव में कम हुए और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ा।

- xiv. क्षति और पाटन के बीच पूर्व में निर्धारित सुरक्षा संबंधी याचिका के अनुसार कोई कारणात्मक संपर्क सिद्ध नहीं था।
- xv. याचिकाकर्ता की बिक्री में घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत में वृद्धि के कारण याचिकाकर्ता के निर्यात में भारी गिरावट की वजह से गिरावट आई।
- xvi. क्षति मार्जिन का परिकलन केवल उन लेन-देनों पर विचार कर किया गया है जो क्षति रहित कीमत से कम है। भारत में क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए भारित औसत की भारित औसत से तुलना की जाती है जिसमें सभी लेन-देन शामिल होंगे। याचिकाकर्ता ने क्षति मार्जिन परिकलन में क्षति निर्धारण में गलती की है। जहां घरेलू उद्योग को आयातों में कीमत की अधिक कटौती अनुभव होती, वहां आयातों को हटाने की अनुमति नहीं है और वह पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.2 के अनुरूप नहीं है।
- xvii. बिक्री कीमत उत्पादन लागत से अधिक थी और घरेलू उद्योग ने सोडियम डाइक्रोमेट की बिक्री पर वर्ष 2015-16 तक लाभ कमाया। उत्पादन लागत और बिक्री कीमत जांच की अवधि में तदनु रूप बढ़ी है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लाभ में गिरावट अविश्वसनीय है।
- xviii. जनहित की जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे बाजार में याचिकाकर्ता एक मात्र व्यापारी होगा और उत्पाद की अधिक लागत होगी। जनहित के मुद्दे का विश्लेषण सुरक्षा जांच परिणाम में भी किया गया था और कम शुल्क नियम के आधार पर उसकी गणना की जा सकती है।
- xix. घरेलू उद्योग सोडियम डाइक्रोमेट की कैप्टिव खपत के संबंध में वास्तविक आंकड़े देने में विफल रहा है क्योंकि वह व्यापारिक बाजार से संबंधित आंकड़ों से भिन्न है। दोनों में अंतर संगत है क्योंकि कैप्टिव प्रयोग के लिए निर्धारित उत्पादन आयातों से सीधी प्रतिस्पर्धा में नहीं आता।
- xx. यह संभव नहीं है कि डाइक्रोमेट पर लाभ में पूर्व वर्ष की तुलना में 2015-16 में 82 प्रतिशत तक गिरावट आई और यह कि व्युत्पन्न सामानों पर लाभ में उसी समय के दौरान वृद्धि हुई। आयातों में भी उसी अवधि में गिरावट आई और इसीलिए वे क्षति का कारण नहीं हो सकते।
- xxi. विष्णु केमिकल्स ने महानिदेशक, सुरक्षा को प्रस्तुत सूचना और अंतिम जांच परिणाम में प्रकट सूचना के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्ष 2013-14 में हानियां सूचित की हैं। तथापि, याचिका में विष्णु केमिकल्स विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्ष 2013-14 के लिए लाभ दर्शा रहा है।
- xxii. कैप्टिव और व्यापारिक बाजार के बीच भिन्नता क्षति विश्लेषण के लिए संगत है क्योंकि कैप्टिव प्रयोग के लिए निर्धारित उत्पादन (घरेलू उद्योग द्वारा) आयातों से सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग सोडियम डाइक्रोमेट की कैप्टिव खपत के संबंध में वास्तविक आंकड़े देने में विफल रहा है, क्योंकि वे व्यापारिक बाजार से संबंधित आंकड़ों से भिन्न हैं।
- xxiii. सोडियम डाइक्रोमेट का उत्पादन और बिक्री राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति आदेशों के अनुसार विनियमित की जाती है। विष्णु केमिकल्स के लिए कई उत्पादों की संस्थापित क्षमता के लिए सहमति आदेश में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

उत्पाद का नाम	क्षमता
सोडियम डाइक्रोमेट	210 टन/दिन
बेसिक क्रोमियम सल्फेट	180 टन/दिन
क्रोमिक एसिड	40 टन/दिन

- xxiv. मूल क्रोमियम सल्फेट और क्रोमियम एसिड सोडियम डाइक्रोमेट के व्युत्पन्न उत्पाद हैं। 0.5 मी. टन सोडियम डाइक्रोमेट 1 मी. टन मूल क्रोमियम सल्फेट (बीसीएस) देता है। 1.6 मी. टन सोडियम डाइक्रोमेट 1 मी. टन क्रोमिक एसिड देता है। इस प्रकार, 180 मी. टन बीसीएस प्रति दिन के उत्पादन में 90 मी. टन प्रति दिन सोडियम डाइक्रोमेट का प्रयोग होगा और 40 मी. टन क्रोमिक एसिड प्रति दिन का उत्पादन करने में 66 मी. टन सोडियम डाइक्रोमेट प्रति दिन का प्रयोग होगा। तदनुसार, कैप्टिव खपत के लिए 156 मी. टन सोडियम डाइक्रोमेट प्रति दिन की आवश्यकता होगी।

- xxv. व्यापारिक बाजार के लिए उपलब्ध सोडियम डाइक्रोमेट केवल 54 मी. टन प्रति दिन (अर्थात् 210 मी. टन प्रति दिन - 156 मी. टन प्रति दिन) है। व्यापारिक बाजार के लिए कुल क्षमता लगभग 17820 मी. टन है (अर्थात् 54 मी. टन * 330 दिन)। यदि विष्णु केमिकल्स 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन करता है तो वह 14256 मी. टन सोडियम डाइक्रोमेट का उत्पादन करने में सक्षम होगा जो कि व्यापारिक बाजार के लिए उपलब्ध होगा।
- xxvi. जांच की अवधि के दौरान व्यापारिक बाजार में कुल घरेलू बिक्री 13853 मी. टन थी। इस प्रकार, कुल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उसकी सोडियम डाइक्रोमेट की घरेलू बिक्री को बढ़ाने की और कोई गुंजाइश नहीं है।
- xxvii. विष्णु केमिकल्स का घरेलू बाजार में सोडियम डाइक्रोमेट के उत्पादन और बिक्री में एकाधिकार है। सोडियम डाइक्रोमेट के आयात पर शुल्क लगाने से निचले उद्योग के लिए आयात गैर-अर्थक्षम होंगे। निचले उद्योग के पास एकाधिकारिक आपूर्तिकर्ता से सोडियम डाइक्रोमेट खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जो कि प्रतिस्पर्द्धक भी है। इससे कई लघु उद्योगों की लागत पर व्यापक रूप से घरेलू उत्पादक को अनुचित लाभ मिलेगा।
- xxviii. सोडियम डाइक्रोमेट का प्रयोग धातु के परिष्कारक उद्योगों, क्षरणरोधी अनुप्रयोगों, जलशोधन रसायनों, पिगमेंट, पेंट, क्रोमियम रसायनों, फार्मास्युटिकल्स (इबुप्रोफेन), वस्त्र (एसिडिक डाइयों के लिए अनुकूल) आदि सहित विभिन्न प्रकार के उद्योग और अनुप्रयोगों में किया जाता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क से विभिन्न प्रकार के निचले उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा।

ज.।।। प्राधिकारी द्वारा जांच

42. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार विभिन्न मानदंडों की जांच की तथा हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया।

ज. संचयी मूल्यांकन

43. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन का मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

(क) संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामानों का पाटन हो रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन के मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक हैं।

(ख) रूस से डी-मिनिमस डंपिंग मार्जिन को ध्यान में रखते हुए, रूस के खिलाफ एडी जांच समाप्त कर दी गई है इसलिए, इस जांच के विषय वाले देश केवल दक्षिण अफ्रीका, कज़ाख़स्तान और तुर्की का गठन करते हैं। तदनुसार, इन संबद्ध देशों से आयात की मात्रा को क्षति विश्लेषण के उद्देश्य के लिया गया है।

(ग) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।

(घ) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात सीधे ही परस्पर प्रतिस्पर्द्धा नहीं करते बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।

45. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के निर्यातों से घरेलू उद्योग को संचयी रूप से क्षति का मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा।

46. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी भी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाएं "..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए". कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत के साथ तुलना में पाटित आयातों से पर्याप्त कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से पर्याप्त मात्रा में कीमतों में अन्यथा कोई कटौती हुई है अथवा कीमत में वृद्धि पर रोक लगी है, जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में हो गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
47. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच की गई और निम्नलिखित रूप में उनको हल किया गया:

ii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

(क) मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

48. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में ध्यान में रखा है। इस प्रकार, मूल्यांकित मांग पूरी क्षति की अवधि में वृद्धि दर्शाती है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। मांग आधार वर्ष की तुलना में पूरी क्षति की अवधि में बढ़ी है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
मांग – कैप्टिव खपत को छोड़कर					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	10,822	13,972	17,938	13,853
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	8,500	8,500	8,500	8,500
संबद्ध आयात	मी. टन	6,046	5,507	4,869	11,360
अन्य आयात	मी. टन	6,565	4,924	4,809	5,044
मांग/खपत	मी. टन	31,933	32,904	36,143	38,758
मांग – कैप्टिव खपत सहित					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	10,822	13,972	17,938	13,853
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	18,447	24,097	26,582	25,740
संबद्ध आयात	मी. टन	8,500	8,500	8,500	8,500
अन्य आयात	मी. टन	6,046	5,507	4,869	11,360
मांग/खपत	मी. टन	6,565	4,924	4,809	5,044
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	50,380	57,001	62,725	64,497

(ख) संबद्ध देशों से आयात मात्रा

49. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या भारत में पूरी मात्रा में अथवा उत्पादन के संबंध में अथवा खपत की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातों में काफी वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि कजाकिस्तान, रूस और तुर्की से आयातित विचाराधीन उत्पाद निर्जल स्वरूप में हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका से आयात तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान शुष्क स्वरूप में होते हैं। संबद्ध सामानों के निर्जल स्वरूप के आयात की मात्रा को प्रत्येक स्वरूप में मानक नमी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए शुष्क स्वरूप में मात्रा में परिवर्तित

किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देशों से शुष्क स्वरूप में संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा का निम्नलिखित रूप में विश्लेषण किया गया है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कजाकिस्तान	मी. टन	2,477	886	909	2,909
दक्षिण अफ्रीका	मी. टन	3,000	4,144	2,418	5,224
तुर्की	मी. टन	568	477	1,568	3,227
संबद्ध देश	मी. टन	6,046	5,507	4,869	11,360
अन्य देश	मी. टन	6,565	4,924	4,809	5,044
कुल आयात	मी. टन	12,611	10,432	9,705	16,405

50. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पूर्ण रूप में आयात जांच की अवधि के दौरान बढ़ा है। संबद्ध देशों से आयातों ने पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि दर्शाई है। आयातों ने 2014-15 से 2015-16 तक गिरावट दर्शाई, परंतु जांच की अवधि में वे काफी बढ़े। तथापि, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि 2014-15 और 2015-16 के दौरान आयातों की मात्रा में गिरावट मुख्यतः सुरक्षा जांच के अनुसरण में सुरक्षा संबंधी शुल्क लगाए जाने की अवधारणा के कारण आई।

(ग) सापेक्ष दृष्टि से संबद्ध देश के आयात

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश का आयात	%	20.77	14.11	10.72	29.41
मांग के संबंध में संबद्ध देश का आयात (कैप्टिव सहित)	%	12	9.66	7.80	17.61
मांग के संबंध में संबद्ध देश का आयात (कैप्टिव को छोड़कर)	%	32.77	22.86	18.42	44.14

51. यह देखा जाता है कि उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में 2015-16 में गिरावट आई, परंतु जांच की अवधि में वे बढ़े। मांग के संबंध में भी संबद्ध आयात कैप्टिव और बिना कैप्टिव दोनों में 2015-16 तक कम हुए, परंतु जांच की अवधि में काफी बढ़े। तथापि, उत्पादन के संबंध में आयातों में आधार वर्ष 2013-14 से तुलना करने पर जांच की अवधि में गिरावट आई है।

(घ) कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
कजाकिस्तान	%	19.64	8.50	9.37	17.73
दक्षिण अफ्रीका	%	23.79	39.72	24.92	31.84
तुर्की	%	4.51	4.58	16.16	19.67
संबद्ध देश	%	47.94	52.80	50.44	69.25
अन्य देश	%	52.06	47.20	49.56	30.75

52. यह देखा जाता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में संबद्ध देशों से पाटित आयातों का हिस्सा देश में कुल आयातों का लगभग 69.25 प्रतिशत है।

(ङ) मांग में बाजार हिस्सा

53. विभिन्न स्रोतों से आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्री पर विचार करते हुए भारत में मांग में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से की जांच की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा 2015-16 तक घटा, परंतु जांच

की अवधि में काफी बढ़ा, जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2015-16 तक बढ़ा और उसके बाद जांच की अवधि में काफी कम हुआ।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग (कैप्टिव के बिना)	%	33.89	42.46	49.63	35.74
अन्य भारतीय उत्पादक	%	26.62	25.83	23.52	21.93
संबद्ध आयात	%	18.93	16.74	13.54	29.31
अन्य आयात	%	20.56	14.97	13.31	13.02
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00
घरेलू उद्योग (कैप्टिव के बिना)	%	58.10	66.79	70.98	61.39
अन्य भारतीय उत्पादक	%	16.87	14.91	13.55	13.18
संबद्ध आयात	%	12	9.66	7.80	17.61
अन्य आयात	%	13.03	8.64	7.67	7.82
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.0

झ. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

54. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि क्या तथाकथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादन की कीमत की तुलना में काफी कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का न्यूनीकरण करने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए अन्यथा है, जो कि सामान्य अवधि में अन्यथा हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संबंध में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की भारित औसत पहुँच लागत से की गई है।

क) कीमत कटौती

55. कीमत कटौती के विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच मूल्य से की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की गणना करते समय सभी कर, छूट, रियायत और कमीशन को हटा दिया गया है और कार्यगत स्तर पर बिक्री वसूली का निर्धारण पाटित आयातों के पहुँच मूल्य से तुलना के लिए किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों का कटौती प्रभाव निम्नलिखित निकलता है:

विवरण	यूनिट	कजाकिस्तान	रूस	दक्षिण अफ्रीका	तुर्की	संबद्ध देश
पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	72,896	74,310	78,898	73,124	75,305
निवल बिक्री वसूली	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	15-20	10-15	5-10	15-20	10-15

क्रम सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	पहुँच मूल्य (रु./मी. टन)	बिक्री कीमत (रु./मी. टन)	कीमत कटौती (रु./मी. टन)	कीमत कटौती %	रेंज
1.	दक्षिण अफ्रीका	मैसर्स लेंक्सेस सीसा प्रा. लि.	मैसर्स लेंक्सेस (पीटीवाई) लि.	***	***	***	***	10-15
2.	तुर्की	मैसर्स सोडा सयानी ए. एस.	मैसर्स सीसाकेम डिस टिकारेट ए. एस.	***	***	***	***	15-20

56. जांच की अवधि में संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है।

ख) कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास

57. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमत न्यूनीकरण करने अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों एवं कीमतों में परिवर्तनों की निम्नलिखित रूप में तुलना की गई:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
उत्पादन की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	90	88	95
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	93	87	92
पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	94	89	82

58. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा उत्पादन लागत, दोनों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। जांच की अवधि में बिक्री कीमत उत्पादन लागत के स्तर से कम है। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में आयातों की पहुँच कीमत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लागत में गिरावट की तुलना में काफी कम हुई है। इस प्रकार, आयातों से केवल ह्रास ही नहीं हो रहा है, बल्कि घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण भी हो रहा है।

ग) कम कीमत पर बिक्री

59. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया गया है और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा निकालने के लिए संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य से उसकी तुलना की गई है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत के संबंध में सत्यापित सूचना और आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। एनआईपी का निर्धारण उस क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर पर विचार करके किया गया है जिसे याचिकाकर्ता संयंत्र में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कच्ची सामग्री के वास्तविक स्तर और यूटिलिटीयों की खपत पर घरेलू उद्योग के उत्पाद के लिए इष्टतम मानदंडों के रूप में विचार किया गया है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक था जो कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है जो नकारात्मक कम कीमत पर बिक्री प्रभाव दर्शाता है:

क्रम सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	पहुँच मूल्य (रु./मी. टन)	एनआईपी (रु./मी. टन)	क्षति मार्जिन (रु./मी. टन)	क्षति मार्जिन %	रेंज
1.	दक्षिण अफ्रीका	मैसर्स लेंक्सेस सीसा प्रा. लि.	मैसर्स लेंक्सेस (पीटीवाई) लि.	***	***	***	***	(10-15)
2.	तुर्की	मैसर्स सोडा सयानी ए. एस.	मैसर्स सीसाकेम डिस टिकारेट ए. एस.	***	***	***	***	(5-10)
3.	दक्षिण अफ्रीका	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	(5-10)
4.	तुर्की	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	0-(5)
5.	रूस	सभी	सभी	***	***	***	***	(5-10)
6.	कजाकिस्तान	सभी	सभी	***	***	***	***	(5-10)

60. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी अधिक है जिससे नकारात्मक कम कीमत पर बिक्री हो रही है।

घ. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

61. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।
62. प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में दिए गए तर्कों को वस्तुपरक रूप से ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की जांच की है।

(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

63. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
संयंत्र क्षमता	मी. टन	39,960	39,960	39,960	63360
उत्पादन	मी. टन	29,105	39,029	45,675	38,624
कैप्टिव खपत	मी. टन	18,447	24,097	26,582	25,740
क्षमता उपयोग	%	73%	98%	114%	60.96%
कैप्टिव खपत से कुल उत्पादन	%	66.38%	61.74%	58.19%	66.64%
बिक्री	मी. टन	10,822	13,972	17,938	13,853
बिक्री से कुल उत्पादन	%	37.18%	35.80%	39.27%	35.86%

(1 वर्ष में 333 प्रचालन देशों के लिए 19.06.2016 तक 120 मी. टन प्रति दिन की दर से और 20.06.2016 से 210 मी. टन प्रति दिन की दर से क्षमता)

64. यह नोट किया जाता है कि:

- क. विष्णु केमिकल्स ने 70,000 मी. टन प्रति वर्ष (210 मी. टन प्रति दिन) की वास्तविक संस्थापित क्षमता का दावा किया है। इसके अलावा, भिलाई संयंत्र (छत्तीसगढ़) में 1600 मी. टन की अतिरिक्त क्षमता थी। परंतु घरेलू उद्योग ने सूचित किया कि 2015-16 से भिलाई संयंत्र में कोई उत्पादन नहीं था। अतः इस संयंत्र को एनआईपी निकालने के लिए ध्यान में नहीं रखा गया है। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीपीसीबी) ने अपने 23.04.2012 के आदेश सं. 7301/पीसीबी/जेडओ-बीएसपी/टेक./2012-58 द्वारा विष्णु केमिकल्स को केवल 120 मी. टन प्रति दिन सोडियम डाइक्रोमेट का उत्पादन करने की सहमति दी थी। वर्ष में 333 कार्य दिवस मानते हुए सोडियम डाइक्रोमेट के लिए क्षमता 39,960 मी. टन प्रति वर्ष निकलती है। इस क्षमता को एपीपीसीबी द्वारा दिनांक 20.06.2016 के सहमति आदेश द्वारा 210 मी. टन सोडियम डाइक्रोमेट प्रति दिन में संशोधित किया गया था। उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी ने 20.06.2016 से सोडियम डाइक्रोमेट के लिए बढ़ी हुई क्षमता को माना है।
- ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन आधार वर्ष से 2015-16 तक बढ़ा और जांच की अवधि में घट गया। क्षमता उपयोग की प्रवृत्ति भी वही रही। हितवद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का जोर निचले उत्पादों पर है। इसके अतिरिक्त, यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में कैप्टिव खपत बढ़ी है और जांच की अवधि में कैप्टिव खपत 66.64 प्रतिशत थी। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कैप्टिव खपत को शामिल करने के बावजूद वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और वांछित क्षमता उपयोग स्तर प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। तथापि, प्राधिकारी यह पाते हैं कि क्षमता उपयोग एपीपीसीबी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण प्रतिबंधित था।
- ग. चूंकि, कंपनी एपीपीसीबी द्वारा सिफारिश की गई उत्पादन सीमा के अंतर्गत ही उत्पादन कर पाई, अतः एनआईपी निकालने के लिए डीजीएडी द्वारा मानी गई संस्थापित क्षमता 20.06.2016 तक 39,960 मी. टन प्रति वर्ष और उसके बाद लगभग 70,000 मी. टन प्रति वर्ष है।
- घ. याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री ने वही प्रवृत्ति नहीं अपनाई है जो उत्पादन की रही है। क्षति की अवधि में उत्पादन में वृद्धि से उसी अनुपात में घरेलू बिक्री में वृद्धि नहीं हुई है। यह देखा जाता है कि जब आयातों में गिरावट थी, तो घरेलू उद्योग की बिक्री बढ़ी और जब जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की वृद्धि हुई तो घरेलू बिक्री में पुनः 2014-15 के स्तरों से नीचे गिरावट आई। यह नोट किया जाता है कि पूरी क्षति की अवधि में घरेलू बिक्री कम रही है।

(ख) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

65. विष्णु केमिकल्स ने महानिदेशक, सुरक्षा के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्ष 2013-14 में हानियां सूचित कीं। तथापि, वर्तमान पाटनरोधी शुल्क याचिका में विष्णु केमिकल्स विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्ष 2013-14 के लिए लाभ दर्शा रहा है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि सुरक्षा याचिका में भिलाई संयंत्र सहित समग्र रूप से खर्चों पर विचार करते हुए सूचना दी गई थी जबकि वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के लिए विजाग संयंत्र की लाभप्रदता का घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया।

66. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
लाभ/हानि – घरेलू	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	394	37	(193)
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	165	101	47
आरओसीई	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	149	117	45

67. उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित नोट किया जाता है:

क. संबद्ध आयात जांच की अवधि में काफी कम कीमत पर बढ़े और उन आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में घरेलू उद्योग उनके समान कीमतें रखने के लिए अपनी बिक्री कीमत कम करने पर मजबूर थे जो कि जांच की अवधि में बिक्री लागत के स्तरों से नीचे चली गई और इसीलिए घरेलू उद्योग को हानियां हुईं।

ख. नकद लाभ 2014-15 में बढ़े, परंतु 2015-16 में घट गए और फिर जांच की अवधि में उनमें गिरावट आई। यही प्रवृत्ति लगाई गई पूंजी पर आय के लिए देखी जा सकती है जो 2014-15 तक बढ़ी, परंतु 2015-16 से नीचे जाने की प्रवृत्ति दर्शाती है और जांच की अवधि में आधार वर्ष में प्राप्त उन स्तरों से काफी नीचे स्तर तक चली गई।

(ग) मांग में बाजार हिस्सा

68. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग (कैप्टिव के बिना)	%	33.89	42.46	49.63	35.74
अन्य भारतीय उत्पादक	%	26.62	25.83	23.52	21.93
संबद्ध आयात	%	38.36	30.90	26.74	41.55
अन्य आयात	%	1.14	0.80	0.11	0.77
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00
घरेलू उद्योग (कैप्टिव सहित)	%	58.10	66.79	70.98	61.39
अन्य भारतीय उत्पादक	%	16.87	14.91	13.55	13.18
संबद्ध आयात	%	24.31	17.84	15.41	24.97
अन्य आयात	%	0.72	0.46	0.06	0.47
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

69. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2015-16 तक बढ़ा, जब आयात मात्रा गिरावट पर थी, परंतु जांच की अवधि में उस समय कम हुआ जब संबद्ध आयात बढ़ गए।

(घ) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

70. क्षति की अवधि में रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
रोजगार	सं.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	111	115	115
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	154	163	160
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	134	157	133
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	121	136	115

71. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में रोजगार का स्तर बढ़ा है और दी गई मजदूरी भी बढ़ी है।

72. उत्पादकता प्रति दिन और उत्पादकता प्रति कर्मचारी दोनों 2015-16 तक बढ़े और घरेलू उद्योग के उत्पादन की गति के अनुरूप जांच की अवधि में कम हुए।

(ड) मालसूची

73. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
प्रारंभिक	मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	168	123	186
अंतिम	मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	182	275	98
औसत	मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	114	185	151

74. यह नोट किया जात है कि घरेलू उद्योग में मालसूची 2015-16 तक बढ़ी, परंतु उसके बाद कम हुई। तथापि, मालसूची का स्तर काफी रहता है।

(च) वृद्धि

75. लाभ, निवेश पर आय, उत्पादन, क्षमता उपयोग और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग की बिक्री नकारात्मक रही है।

क्रम सं.	वृद्धि	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	उत्पादन	%		34%	17%	-15%
2	घरेलू बिक्री मात्रा	%		29%	28%	-23%
3	क्षमता उपयोग	%		25%	16%	-53%
4	घरेलू बिक्री कीमत	%		-7%	-6%	6%
5	लाभप्रदता	%		205%	-93%	-768%
6	नकद लाभ	%		65%	-39%	-54%
7	नियोजित पूंजी पर आय	%		1%	-1%	-2%

(छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

76. घरेलू उद्योग ने दावा किया कि उसकी वित्तीय स्थिति की वर्तमान हालत उसे नए निवेश के लिए पूंजी जुटाने की अनुमति नहीं देते।

(ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

77. उत्पाद के लिए मांग में पूरी जांच की अवधि में निरंतर वृद्धि देखी गई है और घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक केवल उत्पादन लागत और आयात कीमतें हैं।

(झ) पाटन मार्जिन की मात्रा

78. संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक ही नहीं है बल्कि ठोस है, रूस के मामले को छोड़कर जहां पाटन मार्जिन न्यूनतम है।

(ट) क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

79. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत को निर्धारित किया है। विचाराधीन एनआईपी को जांच की

अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग की एनआईपी निकाली गई है और क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए प्रत्येक संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना के लिए उस पर विचार किया गया है। एनआईपी को निर्धारित करने के लिए, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटीयों के साथ भी समान उपचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग के बारे में विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन का परिकलन सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए किया गया है और वही उत्पादन प्रति यूनिट निर्धारित लागत निकालने के लिए माना गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत में कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को प्रभावित नहीं किया गया हो। विचाराधीन उत्पादों के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति सहित औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (पूर्व कर @ 22%) को एनआईपी प्राप्त करने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी, जैसाकि अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है और अपनाया जा रहा है। क्षति मार्जिन को निर्धारित करने के लिए इस प्रकार निर्धारित क्षति रहित कीमत की संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमतों के साथ निम्नानुसार तुलना की गई है:

क्रम सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	पहुँच मूल्य (रु./मी. टन)	एनआईपी (रु./मी. टन)	क्षति मार्जिन (रु./मी. टन)	क्षति मार्जिन %	रेंज
1.	दक्षिण अफ्रीका	मैसर्स लेंक्सेस सीसा प्रा. लि.	मैसर्स लेंक्सेस (पीटीवाई) लि.	***	***	***	***	(10-15)
2.	दक्षिण अफ्रीका	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	(5-10)
3.	तुर्की	मैसर्स सोडा सयानी ए. एस.	मैसर्स सीसाकेम डिस टिकारेट ए. एस.	***	***	***	***	(5-10)
4.	तुर्की	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	0-(5)
5.	रूस	सभी	सभी	***	***	***	***	(5-10)
6.	कजाकिस्तान	सभी	सभी	***	***	***	***	(5-10)

यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी अधिक है जिससे नकारात्मक क्षति मार्जिन हो रही है।

(ठ) कारणात्मक संपर्क और अन्य कारक

80. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के वास्तविक क्षति, मात्रा और कीमत प्रभाव की मौजूदगी की जांच उसकी कम कीमत पर बिक्री तथा कीमत न्यूनीकरण और ह्रास प्रभावों की दृष्टि से करते हुए भारतीय नियमावली और पाटनरोधी करार के तहत सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक मानदंडों की जांच यह देखने के लिए की गई कि क्या पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति कर सकता है। तदनुसार, निम्नलिखित मानदंडों की जांच की गई है:

- संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य:** संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है। चाहे मात्रा न्यूनतम है अथवा कीमत अधिक है।
- मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में संबद्ध सामानों के लिए बढ़ी हुई मांग के बावजूद घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान अप्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ा है। संबद्ध सामानों की खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। मांग में संभावित संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती।

- iii. **प्रौद्योगिकी में विकास:** किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किया और इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकती है।
- iv. **व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ और विभिन्न स्रोतों से आपूर्ति की प्रतिस्पर्धा:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामान भारत में किसी भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों के अधीन नहीं रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, उस प्रतिस्पर्धा के अलावा जो किसी बाजार अर्थव्यवस्था में स्पष्ट है, कोई परस्पर प्रतिस्पर्धा अथवा विभिन्न घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से आपूर्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा ऐसा कोई प्रभाव नहीं दर्शाती जो घरेलू उद्योग को क्षतिकारक के रूप में मानी जा सके।
- v. **निर्यात निष्पादन:** घरेलू उद्योग का संबद्ध सामानों का काफी निर्यात नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग का निष्पादन घरेलू एवं निर्यात बाजार के लिए पृथक् रखा गया है। अतः निर्यात निष्पादन में कोई संभावित गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षति के दावे का कारण नहीं हो सकती।

(ड) कारणात्मक संपर्क स्थापित करने वाले कारक

81. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध को निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध नहीं किया गया है:
 - क. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना में अधिक है।
 - ख. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच मूल्य से अपेक्षाकृत अधिक है।
 - ग. संबद्ध देशों से पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना में अधिक है।

(ढ) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध

82. प्रकटन पश्चात अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं। उनमें उठाए गए अधिकांश मुद्दों को जांच की अवधि के दौरान पहले ही उठाया गया है और उपयुक्त उसका समाधान उपयुक्त रूप से कर दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

83. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के पश्चात किए गए अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:
 - क. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट की अगोपनीय पाठ को प्रकट करें जिससे कि घरेलू उद्योग पाटन के संबंध में सार्थक टिप्पणियाँ दे सके। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्रों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों की प्रति उपलब्ध कराई है।
 - ख. घरेलू उद्योग ने उस समायोजन योजना के कार्यान्वयन के बारे में उल्लेख किया है जिसके फलस्वरूप उत्पादन और क्षमता के उपयोग में वृद्धि तथा ऊपरी शीर्ष लागत में कटौती हुई होती जिसके फलस्वरूप लागत में और अधिक गिरावट होती। उसका प्रस्ताव सुरक्षात्मक जांच के समय किया गया था। हालांकि, सुरक्षात्मक शुल्कों को लगाया नहीं गया था और सुरक्षात्मक शुल्कों को लगाए जाने के माध्यम से एक समान अवसर प्रदान नहीं करने के बावजूद घरेलू उद्योग ने क्षति उठाना जारी रखते समय समायोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए अभी भी प्रयास किए। घरेलू उद्योग ने कार्बन डाई ऑक्साइड अम्लीकरण संयंत्र संस्थापित किया है और उसकी जांच प्रचालन भी हो चुकी है। चूंकि, इस समायोजन योजना में दो चरणों की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का दूसरा चरण अर्थात् कार्बन डाई ऑक्साइड वसूली संयंत्र की संस्थापना अभी शुरू की जानी है और यह आशा है कि इसे लगभग दो वर्षों में शुरू किया जाएगा। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह घरेलू उद्योग पर उस रूप में विचार करे जिस प्रकार से यह मौजूद है और साथ ही इस बात की भी जांच करे कि क्या घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुरक्षात्मक शुल्क जांच के अंतर्गत सभी स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों के विरुद्ध विशिष्ट स्रोतों से पाटित आयातों के कारण क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

- ग. इस क्षमता पर विचार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.04.2012 के एपीपीसीबी आदेश सं. 7301/पीसीबी/जेडओ-वीएसपी/टेक/2012-58 के आधार पर किया गया है। हालांकि, एपीपीसीबी द्वारा बाद में दिनांक 23.07.2014 के पत्र सं. 1475/पीसीबी/आरओ-वीएसपी/2014-3628 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण पर उपयुक्त रूप से विचार नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की कुल क्षमता (कैप्टिव और मर्चेट बिक्री दोनों) पर विचार जांच की अवधि सहित समग्र क्षति की अवधि के दौरान 70000 मी. टन के रूप में किया जाए। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि विजाग, एसडीसी संयंत्र की निवल निर्धारित परिसंपत्ति गिरावट और न कि वृद्धि दर्शा रही है (ह्रास की वसूली के कारण)। इसके अलावा, यह दर्शाता है कि क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। एपीपीसीबी ने केवल उन क्षमताओं के बारे में उल्लेख किया है जिसका उपयोग एक अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए मर्चेट बिक्री और कैप्टिव खपत के लिए किया जा सकता है।
- घ. प्रकटन विवरण में 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की क्षमता के लिए गलत आंकड़ों पर विचार किया गया है और घरेलू उद्योग ने उस संयंत्र की क्षमता के संबंध में दिनांक 28 मई, 2018 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किए हैं जिस पर वर्तमान उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए। दिनांक 23.04.2012 के पीसीबी प्रमाण पत्र संख्या 7301/पीसीबी/जेडओ-वीएसपी/टेक/2012-58 के माध्यम से सूचित की गई क्षमता जिसमें कैप्टिव खपत के लिए अपेक्षित क्षमता शामिल नहीं थी और जबकि कैप्टिव आवश्यकताओं सहित इस क्षमता की सूचना दिनांक 20.06.2016 के पीसीबी के आदेश के माध्यम से दी गई है। पीसीबी के दिनांक 23.04.2012 के प्रमाण-पत्र जिसमें कैप्टिव खपत को छोड़कर क्षमताओं को दर्शाया गया, तब से पीसीबी प्रमाण-पत्र को दिनांक 23 जुलाई, 2014 के दस्तावेज के माध्यम से स्पष्ट किया गया था जिसमें यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि घरेलू उद्योग की 210 एमटीपीडी की निर्माण क्षमता है परंतु बिक्री के योग्य संबंधित उत्पाद की मात्रा 120 एमटीपीडी है जो इस क्षमता को 70000 मी. टन के रूप में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बनाता है (कैप्टिव खपत सहित)। उक्त स्पष्टीकरण याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 22 मई, 2018 के हमारे पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था जिस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। स्पष्ट तौर पर, उक्त पत्र में उल्लिखित 120 मी. टन की क्षमता में 90 मी. टन सोडियम डाइक्रोमेट जिसे कंपनी बेसिक क्रोम सल्फेट के उत्पादन के लिए उत्पादन कर सकती है, शामिल नहीं है। 1 मी. टन बेसिक बाइक्रोम सल्फेट के उत्पादन के लिए 0.50 मी. टन सोडियम डाइक्रोमेट की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता के पास 180 मी. टन बेसिक बाइक्रोमेट सल्फेट की क्षमता है जिसके लिए याचिकाकर्ता को 90 मी. टन सोडियम डाइक्रोमेट की आवश्यकता है। इस प्रकार से, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस पत्र के माध्यम से बिक्री के लिए 120 मी. टन सोडियम डाइक्रोमेट और बेसिक क्रोम सल्फेट के उत्पादन में खपत के लिए 90 मी. टन सोडियम डाइक्रोमेट पर विचार किया गया।
- ङ. यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी स्थिति में यदि क्षमता पर विचार कैप्टिव खपत को छोड़कर किया जाता है तब उत्पादन पर भी निश्चित रूप से विचार कैप्टिव खपत को छोड़ने के बाद ही किया जाना चाहिए। जबकि जून, 2016 तक क्षमता में कैप्टिव खपत के लिए क्षमता शामिल नहीं है, विचार किए गए उत्पादन में कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन शामिल है। यह उपयुक्त नहीं है कि कैप्टिव खपत को छोड़कर क्षमता और कैप्टिव खपत सहित को शामिल करते हुए उत्पादन पर विचार किया जाए। क्षमता का उपयोग सतत वृद्धि को दर्शाएगा यदि कैप्टिव खपत को उत्पादन से बाहर कर दिया जाए। इस प्रकार से, क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षमता के उपयोग का कोई सामान्यीकरण नहीं हो सकता है।
- च. घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि सभी संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन, जिसे प्राधिकारी द्वारा तय किया गया है, सकारात्मक और न्यूनतम स्तरों से ऊपर है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होती है कि तय किये गए सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत के आधार पर किया गया है। जैसा कि ऊपर में अनुरोध किया गया है, घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में संशोधन ऊपर में उल्लेख किए गए कारणों से किया जाना अपेक्षित है। जैसे ही घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में संशोधन किया जाएगा, सीएनवी को भी संशोधित किए जाने की आवश्यकता होगी।
- छ. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति उठानी पड़ रही है क्योंकि कैप्टिव खपत के साथ अथवा उसके बिना क्षति में क्षति की जांच की समग्र अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। दूसरे, 2013-14 से 2015-16 तक आयात की मात्रा में गिरावट आई, परंतु जांच की अवधि के दौरान इसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई। संबद्ध आयातों में यह गिरावट इस कारण से हुई थी कि सुरक्षात्मक शुल्कों को लगाए जाने की आशंका थी। इसके अलावा, आयात की मात्रा में 2013-14 से 2015-16 तक गिरावट आई, परंतु जांच की अवधि के दौरान इसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

- ज. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होती रही है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा उत्पादन की लागत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट हुई, परंतु बिक्री की कीमत में गिरावट उत्पादन की लागत में गिरावट की तुलना में बहुत अधिक हुई है। संबद्ध आयातों के पहुँच मूल्य में क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान गिरावट आई और यह जांच की अवधि में अपने न्यूनतम स्तर पर था। इसके फलस्वरूप संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी और दबावकारी प्रभाव पड़ा है।
- झ. घरेलू उद्योग की क्षमता का निर्धारण गलत रूप से किया गया है, जैसा कि ऊपर में प्रस्तुत किया गया है। एपीपीसीबी के आदेशों की गलत व्याख्या के कारण गलत क्षमता आंकड़ों पर विचार करना पड़ा है जिसके कारण क्षमता के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जो बाद में क्षति रहित कीमत पर दर्शाया गया। निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया गया है कि वे प्रकटन विवरण के रूप में यथानिर्धारित वर्तमान क्षमताओं के रूप में घरेलू उद्योग की क्षमताओं के लिए गणना और बनावट पर विचार करें, यह घरेलू उद्योग की गलत तस्वीर को दर्शाता है।
- ञ. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि अधिकांश आर्थिक मानदंडों द्वारा पाटन के प्रभाव को दर्शाने तथा कंपनी द्वारा नकारात्मक वृद्धि का नुकसान उठाने के बावजूद एपीपीसीबी आदेशों की गलत व्याख्या के फलस्वरूप क्षमता के स्तरों और उसके परिणामस्वरूप क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन की गलत गणना की गई।
- ट. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया गया है कि अमेरिकी डॉलर के मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए। रुपए में बहुत अधिक गिरावट आ रही है और इस कारण से निश्चयात्मक शुल्कों को कृपया अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किया जाए। भारतीय रुपए में हास का प्रभाव कच्चे माल, यूटिलिटी की लागतों तथा अन्य लागतों पर पड़ा है। इसकी पुष्टि चीन के मेटकोक के मामले में सेसटेट के निर्णय में निहित तर्क द्वारा भी किया गया है। इस शुल्क को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करते समय, माननीय सेसटेट ने निम्नलिखित उल्लेख किया:

"धारा 9क में यह शर्त रखी गई है कि पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार से इस कानून का आशय और उद्देश्य घरेलू उद्योग को उन दरों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए है जो पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से अधिक न हो। इस कारण से हमारा यह दृढ़ मत है कि पाटनरोधी शुल्क को डॉलर के रूप में ही तय किया जाना चाहिए जिससे कि सुरक्षा की मात्रा में कमी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण न हो सके। वर्तमान मामले में आवेदक घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया है कि सुरक्षा का स्तर अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए में गिरावट के कारण अंतिम जांच परिणाम के समय 19 अमेरिकी डॉलर से अधिक से गिरकर अब तक 16 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। पाटनरोधी शुल्क के उद्देश्य से इसे लागू करना आवश्यक है और इस कारण से यह कानून के अनुरूप है।"

निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

84. निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के बाद निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- मैसर्स सोडा सनायी ए. एस. ने यह उल्लेख किया है कि उनकी घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसकी बजाए निर्यातकों का यह अनुरोध है कि सामान्य मूल्य की गणना निर्यातकों की तीसरे देश में बिक्री अथवा उचित लाभ के साथ लागत के आधार पर किया जाना चाहिए।
 - मैसर्स लेंक्सेस (पीटीवाई) लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका ने यह अनुरोध किया है कि इसने पाटित कीमतों पर भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और भारत में ये कीमतें बिल्कुल सही हैं, वाणिज्यिक बाजार की कीमतों के आस-पास हैं। उसको देखते हुए, यह टिप्पणी कि पाटन होता रहा है और पाटन मार्जिन की टिप्पणी तथा यह टिप्पणी भी कि हमारे ग्राहक कीमत में कटौती करने में लगे हुए हैं, आधारहीन है।
 - मैसर्स आक्ट्यूर्विस्क क्रोमियम केमिकल प्लांट्स, कजाकिस्तान ने यह अनुरोध किया है कि सोडियम डाइक्रोमेट का जलीय रूप और गैर-जलीय रूप केवल विचाराधीन उत्पाद के दो अलग-अलग रूप हैं जिसका उल्लेख प्रकटन विवरण में किया गया है। इस उत्पाद का "गैर-जलीय" रूप का परिवर्तित रूप जिसमें मामूली नमी होती है और जिसका निर्यात कजाकिस्तान से होता है और जो घरेलू उद्योग द्वारा यथा उत्पादित "ड्राई हाइड्रेट" रूप में है, के कारण संबद्ध वस्तुओं की मात्रा कम हो गई है और उसी स्तर पर उसमें शुद्धता रखना एक सही दृष्टिकोण नहीं है और यह एकतरफा है। सोडियम डाइक्रोमेट के गैर-जलीय रूप का अण्वीय भार 261.965 ग्राम/अणु और सोडियम डाइक्रोमेट का जलीय रूप का अण्वीय भार 298 ग्राम/अणु है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वह पद्धति उपलब्ध नहीं कराई है जिसे इसने गैर-जलीय सोडियम डाइक्रोमेट की मात्रा को ड्राई-हाइड्रेट सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित करने के लिए अपनाया है।

- iv. मैसर्स विष्णु केमिकल्स पर विचार पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस परिभाषा के अपवाद में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग को कथित पाटित उत्पाद का आयातक नहीं होना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता अन्य देशों से कूड क्रोम ओर का आयातक है और यह उस ओर को जलीय सोडियम डाइक्रोमेट में बदलने का प्रयास कर रहा है। चूंकि, उपलब्ध कच्चे माल का आयात विदेश से किया जाता है, अतः याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग नहीं होता है।
- v. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि यह उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कर सकता है और लागत में कमी कर सकता है। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में जांच की अवधि में कटौती हुई थी। यह उत्पादन कम ही था जिसके कारण घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत में प्रभावी रूप से कटौती नहीं कर पाया।
- vi. रिकार्ड में दर्ज करने के लिए यह एक मामला है कि घरेलू उद्योग 2012-13 से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण क्षति के बारे में आरोप लगाता रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग ने उक्त वर्ष में सुरक्षा संबंधी प्राधिकारी से भी संपर्क किया था। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिकार्डों और आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन और लाभ में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही थी और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई थी। केवल यह तथ्य कि घरेलू उद्योग की बिक्री और उत्पादन जांच की अवधि में कम हो गए थे और आयातों की मात्रा में वृद्धि क्षति और संबद्ध आयातों के बीच एक कारणात्मक संबंध सिद्ध नहीं करता है। विचाराधीन उत्पाद की लागत प्रभावी रूप से कम करने के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता, कैप्टिव उत्पादन, क्रोम ओर की अनुपलब्धता, क्रोम ओर की कीमतों सहित ऐसे अनेक अन्य कारक थे जिस पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- vii. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन लागत प्रभावी रूप में करने में सक्षम नहीं है और नई प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित करने के बजाए, घरेलू उद्योग का उद्देश्य यह है कि बाजार से प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमतों में और अधिक वृद्धि होगी तथा घरेलू उद्योग को अनुचित और गैर-प्रतियोगी लाभ मिलेगा क्योंकि घरेलू उद्योग कैप्टिव रूप में अपने विचाराधीन उत्पाद की खपत करता है और इसके डाउनस्ट्रीम उत्पाद का उत्पादन अपेक्षाकृत कम लागतों पर किया जाएगा।
- viii. यह अनुरोध किया गया है कि प्रकटन विवरण में सूचना के उपलब्ध स्रोतों के बारे में कोई सूचना शामिल नहीं है जिसके आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कजाकिस्तान के उत्पादों की निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उपयोग में लाए गए अन्य स्रोतों का भी उल्लेख नहीं है जिसे कजाकिस्तान से उत्पादों के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया है।
- ix. निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार नहीं कर सके हैं कि मैसर्स विष्णु कंपनी की याचिका जिसके आधार पर जांच शुरू की गई थी, का समर्थन पर्याप्त, स्वीकार्य और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा किया गया हो। इस संबंध में मैसर्स एसीसीपी का यह मत है कि जांच को पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 5 पर विचार किए बिना शुरू किया गया है।
- x. यह अनुरोध किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क की कोई सकारात्मक सिफारिश संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में क्षति के नकारात्मक मार्जिन के कारण नहीं की जा सकती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सभी संबद्ध आयातों के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। इस कारण से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है जिसे समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। पाटनरोधी जांचों अर्थात् (क) चीन, बेलरूस, उक्रेन एवं पेरू से एक्रिलिक फाइबर, (ख) मलेशिया, भारत, चीन और सऊदी अरब एवं थाइलैंड से न बुने हुए फैब्रिक में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिकांश संबद्ध आयातों के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है जिसके फलस्वरूप निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इन सभी मामलों में संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की और इस मामले में भी वही सतत प्रथा अपनाई जाए।
- xi. निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग के प्रमुख आर्थिक मानदंडों तथा रोजगार, मजदूरी और प्रति दिन उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता, माल भंडार एवं लाभ/हानि के लिए वास्तविक और सूचीबद्ध आंकड़े उपलब्ध कराए।
- xii. मैसर्स विष्णु केमिकल्स और अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से का प्रकटीकरण भी इस बात की पुष्टि करता है कि विष्णु केमिकल्स घरेलू बाजार में बिक्री करने के लिए इच्छुक नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह टिप्पणी भी की है कि मैसर्स विष्णु केमिकल्स द्वारा उत्पादन जांच की अवधि में कुल उत्पादन का 82 प्रतिशत होता है। हालांकि, इसका नियंत्रण जांच की अवधि में केवल 35.74 प्रतिशत बाजार हिस्से पर है। अन्य भारतीय उत्पादक जिनका हिस्सा कुल उत्पादन का 18 प्रतिशत है, ने जांच की अवधि में 21.93 प्रतिशत बाजार हिस्से पर कब्जा किया जो स्पष्ट रूप से यह

दर्शाता है कि मैसर्स विष्णु केमिकल्स सोडियम डाइक्रोमेट के डाउनस्ट्रीम उत्पादों और न कि सोडियम डाइक्रोमेट की बिक्री बढ़ाने और लाभ अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

85. यह नोट किया जाता है कि हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्राथमिक रूप से प्रकटन विवरण के संदर्भ में उनके द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोध की पुनरावृत्ति हैं। संगत विरोधी दृष्टिकोण और अनुरोधों का अन्य बातों के साथ-साथ समाधान इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त खंडों के अंतर्गत किया गया है जो संगत तथ्यों के मूल्यांकन और संगत नियमों को देखते हुए तथा प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यायपूर्ण निर्णयों के आधार पर अपने-आप में स्पष्ट है। फिर भी इन पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में की गई कुछ टिप्पणियों का समाधान नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:
- i. घरेलू उद्योग की अपर्याप्त सूचना जिसे उनके द्वारा विधिवत प्रस्तुत की गई है, के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस आवेदन में जांच आरंभ करने के उद्देश्य से सभी संगत सूचना निहित है। प्राधिकारी ने इस संतुष्टि की कि इस आवेदन में जांच को आरंभ करने का औचित्य बताने के लिए पर्याप्त साक्ष्य निहित हैं, के बाद ही वर्तमान जांच को आरंभ करने का निर्णय लिया।
 - ii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर मिश्रित और डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं को ठीक करने और इसके क्षति कारक प्रभाव का समाधान घरेलू उद्योग को समान अवसर उपलब्ध कराकर करना है। इसके अलावा, पाटनरोधी उपायों को लगाने से, यदि लगाया गया, आयातों में रुकावट नहीं होती है। हालांकि, आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध रहेंगे और यह घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को भी बनाए रखेगा।
 - iii. जहां तक हितवद्ध पक्षकारों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावे का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत गोपनीयता के दावे के अध्यक्षीन संगत सूचना प्रकट नहीं की है, हालांकि, इन अनुरोधों का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया है। हालांकि, आवेदक विशिष्ट गोपनीय सूचना उन्हें पाटन मार्जिन और क्षति रहित कीमत के संबंध में दी गई है।
 - iv. जहां तक उत्पाद के गैर-जलीय रूप से डाई हाइड्रेट रूप में परिवर्तन किए जाने के संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंता का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि इस मामले की जांच की गई है और इस पर विचाराधीन उत्पाद शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त अनुच्छेद में विचार-विमर्श किया गया है। हालांकि, यह दोहराया जाता है कि यह परिवर्तन उसी स्तर पर विभिन्न मानदंडों की जांच करने के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के दो रूपों के अण्वीय भार के अनुपात के आधार पर किया गया है।
 - v. जहां तक विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन क्षमता की गणना का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि इस मुद्दे का विस्तार से समाधान इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थान पर किया गया है। हालांकि, इसे पुनः दोहराया जाता है कि प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, क्षमता और क्षमता का उपयोग, दोनों का निर्धारण इस जांच परिणाम में क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से किया गया है।
 - vi. जहां तक संरचित सामान्य मूल्य के निर्धारण का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि इसे गैर-सहयोगी निर्यातकों के लिए घरेलू उद्योग के खपत मानदंड और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार करने के बाद किया गया है। तदनुसार, रूस और कजाकिस्तान के लिए संरचित सामान्य मूल्य तय किया गया है और पाटन मार्जिन में संशोधन किया गया है। रूस से आने वाले डी-मिनिस पाटन मार्जिन को देखते हुए, रूस के खिलाफ पाटनरोधी जांच समाप्त कर दी गई है। इसलिए, इस जांच में विषय देश अब केवल दक्षिण अफ्रीका, कज़ाखस्तान और तुर्की का गठन करते हैं। इसलिए, पाटन और क्षति के संबंध में जानकारी उचित पैरा में संशोधित की गई है। हालांकि, प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर सहकारी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।
 - vii. जहां तक गैर-सहयोगी निर्यातकों को निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए सूचना के स्रोत को प्रकट करने का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विचार इस जांच परिणाम में निर्यात कीमत के निर्धारण और क्षति के विश्लेषण के लिए किया गया है।

- viii. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों की संघटक घरेलू उद्योग के उनके दावे के संबंध में चिंता व्यक्त करने का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, मैसर्स विष्णु केमिकल्स को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है क्योंकि वे जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातक नहीं हैं।
- ix. जहां तक सूचकांक संबंधी आंकड़ों को प्रकट करने का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि जहां भी यह संगत और उपयुक्त है, या तो मात्रा अथवा सूचकांक संबंधी आंकड़ों को इन आवेदकों की गोपनीयता बनाए रखते हुए इस जांच परिणाम में प्रकट किया गया है जो अन्य प्रकार से उनके व्यापारिक हित पर प्रभाव डालते।
- ण. निष्कर्ष एवं सिफारिशें**
86. उठाए गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा इस अंतिम जांच परिणाम में रिकार्ड किए गए अनुसार प्राधिकार के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- (1) विचाराधीन उत्पाद को दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और तुर्की से उनके सामान्यमूल्य से कम पर भारत को निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।
 - (2) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण आर्थिक क्षति नहीं हुई है।
 - (3) संबद्ध देशों से आयातों घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं।
 - (4) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं समझते हैं और एतद्वारा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 11 (2) के साथ पठित नियम 14 (ख), (ग) और नियम 17 (1) (3) के अनुसार वर्तमान जांच को समाप्त करते हैं।
- त. आगे की प्रक्रिया**
87. इस अंतिम जांच परिणाम के कारण उत्पन्न होने वाली केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2018

FINAL FINDINGS

(Case No. O.I/09/2017)

Subject: Final Findings in the Anti-dumping investigation concerning imports of Sodium Dichromate originating in or exported from Russia, South Africa, Kazakhstan and Turkey.

F. No. 6/4/2017 –DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof:

71. Whereas M/s Vishnu Chemicals Limited (hereinafter also referred to as the Petitioner or Applicant) has filed an petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of "Sodium Dichromate" (hereinafter also referred to as the

subject goods or PUC) from Russia, South Africa, Kazakhstan and Turkey (hereinafter also referred to as the subject countries).

72. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, issued a public notice vide Notification No.6/4/2017-DGAD dated 4th July, 2017, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with the sub rule 5 of the above Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. **PROCEDURE**

73. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
- (i) The Authority notified the Embassies of the Subject Countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - (ii) The Authority issued a public notice dated 4th July, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
 - (iii) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the Subject Countries in India, known producers/exporters from the subject Countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
 - (iv) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject Countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - (v) The Embassies of the subject Countries in India was also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
 - (vi) The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

S.N.	Name of the Company
South Africa	
1.	a) M/s Lanxess Cisa Pvt. Ltd. b) M/s Lanxess (Pty) Ltd
Russia	
2.	M/s Nova Chrome
Turkey	
3.	a) M/s Sisecam Dis Ticaret A.S. b) M/s Soda Sanayii A.S
Kazakhstan	
4.	M/s JS Aktyubin Sk Chromium

- (vii) In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:
- (i) M/s Lanxess Cisa Pvt. Ltd. (producer), South Africa
 - (ii) M/s Lanxess (Pty) Ltd (exporter), South Africa.
 - (iii) M/s Soda Sanayii A.S (producer), Turkey

(iv) M/s Sisecam Dis Ticaret A.S, Turkey.

(viii) The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

SN	Name of the Company	SN	Name of the Company
1.	M/s Anupam Colors and Chemicals	2.	M/s Anupam Colors
3.	M/s Swati Petro Products Pvt Ltd	4.	M/s Solar Chemferts Pvt Ltd
5.	M/s Raveshia Colours Pvt Ltd.	6.	M/s A.S. Enterprises
7.	M/s Mica Organics Ltd.	8.	M/s Sudarshan Chemical Industries Ltd
9.	M/s Shri Vardayani Chemical Industries Ltd.	10.	M/s Ridhi Pharma
11.	M/s Vapi Pigments Chemicals & Alted Products	12.	M/s Vapi Oxides and Colours Ltd.
13.	M/s Colour Chromes Pvt. Ltd.	14.	M/s KN Chemicals
15.	M/s Indo Tan Chemicals Ltd.	16.	M/s Shasun Chemicals and Drugs Ltd
17.	M/s Industrial Organics Limited (Formerly Trident Alco-Chem Limited)		

(ix) In response, the following importers/users have responded and filed importer's questionnaire response:

- i. M/s Micas Organics
- ii. M/s Strides shasun Ltd.
- iii. M/s GEE international
- iv. M/s Voxcon Pigments and chemicals Pvt Ltd
- v. M/s IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
- vi. M/s Aishwarya Mechfo (India) Pvt. Ltd
- vii. M/s Colour Chromes Pvt. Ltd
- viii. M/s Sona Synthetics Products
- ix. M/s Sudarshan Chemical Industries Limited
- x. M/s Anupam colours Private Limited
- xi. M/s Anupam Colours & Chemicals Industries
- xii. M/s Solar Chemferts Pvt Ltd

(x) Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been received on behalf of the following parties during the course of this investigation. However, no importer/exporter's questionnaire have been filed by the following parties.

- i. The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India.
- ii. JSC Aktyubinsk Chromium Chemicals Plant, Kazakhstan.
- iii. JSC NPCC, Russia
- iv. Swati Petro Products Pvt. Ltd.
- v. Skystep Trading Ltd.
- vi. Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan and the First Vice Minister.
- vii. Russian Federation the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation.

(xi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

(xii) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

- (xiii) The Non-injurious Price (NIP) based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- (xiv) Table study for the Verification of the information provided by the applicant domestic industries, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present final findings.
- (xv) Table study of the information provided by the producers/exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and has been relied upon for the purpose of present final findings.
- (xvi) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is for the period from 1st April, 2016 to 31st March, 2017 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI.
- (xvii) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 26th March, 2018. All the parties who had attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were advised to offer their rebuttals.
- (xviii) The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present final findings.
- (xix) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final findings.
- (xx) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- (xxi) In view of the de-minimis dumping margin from Russia, AD investigation against Russia has been terminated. Therefore, the subject countries in this investigation now constitute only South Africa, Kazakhstan and Turkey.
- (xxii) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- (xxiii) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs 67.95

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

B.1 Submissions made by the Domestic Industry

- 4 The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
 - i. The product under consideration in the present investigation is “‘Sodium Dichromate’ or ‘Sodium Dichromate’ in anhydrous and di-hydrate form” (hereinafter referred to as ‘subject goods’ also). Chemical formula of the product under consideration is “Na₂Cr₂O₇”. The only difference between Sodium dichromate di-hydrate form and sodium dichromate anhydrous form is of the moisture content in the two.
 - ii. Sodium dichromate is used as an oxidizing agent for many organic synthesis and bulk drugs especially ibuprofen production. It is used in metal finishing industries, anti-corrosive applications, water treatment chemicals, pigments, paints etc. It is also used in manufacture of other chromium chemicals.
 - iii. Petitioner produces sodium dichromate in dihydrate form, which has moisture content to the tune of around 11-12%. The imports from South Africa are also in di-hydrate form; whereas, the imports from Russia, Turkey and Kazakhstan are in the anhydrous form having minimum moisture. Therefore, the moisture level has been proportionately adjusted in order to enable fair comparison between the domestically produced product and the imported product.
 - iv. The only difference between di-hydrate form and anhydrous form is of the moisture content in the two. The product under consideration is first produced in solution form, wherein dichromate content is in the region of 50%. In order to save on transportation cost, the moisture is evaporated and reduced to 11-12% by some

producers and to 0.5% by others. Whatever be the moisture content of the product, the first process at the consumer's end is to dilute the product again in the region of 50% before use in the production process. Since the product is used by the consumers for the content of dichromate present in it and if dichromate content is higher, it only means proportionately lower consumption.

- v. Consumers in all segments have been using sodium dichromate produced by the applicant which clearly shows that there is no difficulty in using the product produced by the applicant and that the products are substitutable with the subject goods imported from the subject countries. Consumers are using the subject goods produced by the domestic industry and exported from subject countries interchangeably.
- vi. The product under consideration is classified under Chapter 28, sub-heading 2841 3000, of the Customs Tariff Act. The Customs Classification is, in any case, indicative and not binding on the scope of the product under consideration

B.2 Submissions made by the other interested parties

5 The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:

- i. There is difference in both the forms of the product. The initiation notification did not highlight the difference between the two forms of the PUC. Pricing, manufacturing, physical and chemical properties are different for these two forms. The two forms of the product are different and the same should not be treated as one single product.
- ii. Product of ACCP varies from PUC on molecular weight, appearance, solubility, specific gravity, heat of solution. ACCP's product has 0.2%-0.4 percentage of moisture and easily distinguishable from PUC. Petitioner falsely states that product of ACCP has negligible moisture.
- iii. The basis for adjustment between the domestic price and the imports has not been provided or substantiated by the domestic industry.
- iv. Domestic industry has misclassified the PUC imported from Russia, Turkey and Kazakhstan by stating that it contains 99% moisture. Imported product from Russia, Turkey and Kazakhstan contains moisture of approximately 2%. Safeguard findings also establish that the hydrated variety is manufactured by the DI which contains 12-14% and imported product is in anhydrous form and it contains approx. 2% moisture.

B.3 Examination by the Authority

6. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry. With respect to the product under consideration, the Authority notes:

- i) The product under consideration is 'Sodium Dichromate' also known as 'Sodium Dichromate' which exists in both the anhydrous and di-hydrate forms. It is used as oxidizing agent for many organic synthesis and bulk drugs especially ibuprofen production. It is used in metal finishing industries, anti-corrosive applications, water treatment chemicals, pigments, paints, etc. It is also used in manufacture of other chromium chemicals.
- ii) As regards the contention of the interested parties that 'Sodium Dichromate' in anhydrous and di-hydrate forms are different products, it is noted that the anhydrous and di-hydrate forms are merely two forms of the product under consideration. The only difference between Sodium dichromate di-hydrate and sodium dichromate anhydrous form is of the moisture content in these two forms. Petitioner produces sodium dichromate in di-hydrate form, which has moisture content to the tune of around 11-12% whereas the imports from Russia, Kazakhstan and Turkey are of anhydrous form of the product which has negligible moisture content. However, imports from South Africa are of di-hydrate form. It is further noted that the end uses, application and the manufacturing process of the two forms are also the same. The consumers are consuming the imported subject goods of both anhydrous/dehydrate forms and domestically produced subject goods of dehydrate form interchangeably. In view of the substitutability and uses of the product, the Authority notes that Sodium Dichromate anhydrous and di-hydrate are merely two forms of the product under consideration i.e. Sodium Dichromate.
- iii) Further, for the purpose of the present investigations and for a fair comparison, the 'anhydrous' form of the product which has negligible moisture as exported from Kazakhstan, Russia and Turkey has been converted to the 'Di-hydrate' form as produced by the domestic industry, to bring volume of subject goods and purity therein at same level. During the course of verification of information filed by the domestic industry and based on the information provided by them, it is noted that dihydrate form of subject good has the molecular weight approximately 298 gm/ mol whereas anhydrous form of the subject goods has the molecular weight approximately as 262 gm/mol. In view of the molecular weight of the two different forms

of PUC due to the moisture content, imports volume from Russia, Kazakhstan and Turkey have been converted from anhydrous to dihydrate sodium dichromate in order to have the fair comparison with domestically produced dihydrous Sodium Dichromate. Based on the examination of the information filed by the interested parties, the Authority confirms the product under consideration is Sodium Dichromate. It is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act under subheading 2841 3000 but, in any case, the same is indicative and not binding on the scope of the product under consideration.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1 Submissions made by the Domestic Industry

7. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:
 - i. The application was filed by petitioner, M/s Vishnu Chemicals Limited, along with two supporters namely, M/s Kanakdurga Chemicals and M/s Konark Chrome Chemicals Ltd. With or without the supporters, the petitioner occupies a major proportion of the total Indian production.
 - ii. The petitioner has neither imported the subject goods from any of the subject countries nor is related to any exporter or producer of the product under consideration from the subject countries.
 - iii. The petitioner has sufficient standing and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.
 - iv. Supporters have provided information relating to production, sales, stocks and capacity. Kanakdurga had to shut down its plant on account of aggressive dumping by the exporters. Petitioner's performance shows that the domestic industry is suffering material injury.

C.2 Submissions made by the other interested parties

8. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:
 - i. Information with regard to the other supporters is unreliable and irrelevant in the current investigation. No producers including the supporters have provided any information and this is merely an attempt by the petitioner to show that the other Indian producers are also affected.
 - ii. Claim of Kanakdurga does not have any merit as it has neither produced the goods in the POI nor has stated if it can restart production.

C.3 Examination by the Authority

9. Rule 2(b) provides as under:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

10. The present application was filed by M/s Vishnu Chemicals Limited and supported by M/s Kanakdurga Chemicals and M/s Konark Chrome Chemicals Ltd. The production of the applicant accounts for 82% of domestic production of like article in India. Further, the applicant is not related to any exporter or importer thereof and has not imported the subject goods itself. As regards the producer wise production of the subject goods, the Department of Chemicals and Petrochemicals stated that department do not monitor the production details of Sodium Dichromate.
11. Based on the examination of information on record shows that the domestic industry's production alone constitutes “a major proportion” of total Indian production. Accordingly, after careful examination of the legal provisions and facts of the case, the Authority, holds that the applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY**D.1 Submissions by the Domestic Industries**

12. With regard to confidentiality, the submissions made by the domestic industry during the course of the investigation are as follows:
- i. The petitioner has claimed only such information as confidential, the confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
 - ii. The petitioner has provided non confidential version of the application in sufficient detail. None of the interested party has been able to bring any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified as per AD Rules.
 - iii. Information with respect to Post invoicing discounts by the interested parties cannot be disclosed as the same has been sourced from a third party, disclosure of which would hamper the business interests of the third party.

D.2 Submissions made by the other interested parties

13. The submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:
- i. Information claimed confidential needs to be verified, as DG Safeguard has disclosed the same information in their safeguard findings which has been claimed confidential.
 - ii. Post invoicing note as held confidential should be disclosed to Lanxess, as it directly pertains to them.

D.3 Examination by the Authority

14. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

15. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
- (i) Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business related information as confidential.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**E.1 Submissions made by the domestic industry**

16. The miscellaneous submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. Domestic industry could not implement adjustment plan as the Safeguard findings were negative and thus the domestic industry continued to suffer injury. Deterioration in performance of the domestic industry could not have been due to possible non-adoption of adjustment plan.
- ii. The request of anti-dumping duty is not against public interest rather the non-imposition of the anti-dumping duty would have devastating effects on the Indian industry than the imposition of the duty. Effect of such low priced imports was seen earlier when 'Kanakdurga' was ousted and forced to shut their business.
- iii. Anti-dumping measure is a measure that is imposed against unfair trade practise. Trade among nations is promoted but it should not be at the cost of dumping/unfair trade practices.
- iv. The pollution control board gives the permit for quantitative production only after considering all the relevant factors and nobody can raise an objection to the same in anti-dumping investigations. The DG safeguard was misled and erred in holding that the petitioner does not have a capacity of 70,000 MT.
- v. As regards reference of imports in Annual Reports of the domestic industry, the information for that period of investigation is of utmost importance. The imports had declined in the period 2014-15, 2015-16 and thus there was no reference to the same in the annual report. Imports increased significantly in the POI and reference has been made to the same. The annual report for POI also states the effect of dumping on the industry.
- vi. DG safeguard finding considered imports as per IBIS whereas the petitioner has considered DGCI&S data in the application. DG Safeguard finding however erroneously states the source as DGCI&S.
- vii. Capacity of the petitioner as provided in the petition is the capacity for the concerned product. The plant was set up for the production of the product concerned and due to absence of orders from the domestic consumers, the petitioner has been forced to produce derivatives of the product concerned.
- viii. As regards the difference of information in AD application and safeguard findings during 2013-14, the domestic industry submitted that capacity was considered by the Safeguard Authority as 55600 MT taking into account the capacity of Bhilai Plant as 16,000 MT also however, the capacity of the Vizag was not correctly computed as per PCB order. However, in this investigation capacity of the Vizag plant has been considered as 70000 MT for the POI as per the consent order of Pollution Control Board which has been duly verified by the Authority. As regards the difference in figures of import volume during the same period, the domestic industry has submitted that DG Safeguard has taken the import volume as per the DGCI&S published data, however, in the present investigation the transaction wise data of the DGCI&S import data has been considered and which has been duly verified. Similarly, the domestic sales in the safeguard investigation was considered as captive transfers from Vishakhapatnam to Bhilai Plant, whereas domestic sales in this investigation consider the same as captive consumption. However, the minute difference is still there due to the reason that closing transfer from Vishakhapatnam to Bhilai has been treated as domestic sales in the safeguard investigation, however, the same has been considered as inventory in AD investigation.
- ix. The domestic industry has submitted, if the safeguard duty is imposed, they will take steps to increases competitiveness. Since the safeguard duty is not imposed, it is not appropriate to expect that the domestic industry will still implement the adjustment plan. However, they have stated that implementation of adjustment plan is already in process. Even though the domestic industry has been trying to implement the adjustment plan given in the safeguard investigation, the domestic industry has not been able to completely implement it. In the process of implementation of adjustment plan the domestic industry has been able to install CO2 acidification plant and trial is being undertaken. However, the CO2 recovery plant is still to install. The complete installation and stabilization of CO2 acidification and recovery process will take at least 2 years, as a cost cutting measure under the adjustment plan. However, the domestic industry has requested the authority to consider the request for imposition of AD duty thereby, they could implement the adjustment plan without any further injury to the domestic industry.

E.2 Submissions made by the other interested parties

17. The submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to miscellaneous issues during the course of the investigation are as follows:

- i. In the safeguard findings, an implementation plan for becoming competitive was submitted. It should be verified if the same has been implemented.
- ii. Report published by the petitioner does not support their own claim of suffering losses. The same report also mentions proposed expansion projects.
- iii. Despite the growing trade volumes between Turkey and India the trade deficit against Turkey has also been growing. The volume of Turkish exports cannot harm Indian market and any dumping measure would likely deteriorate trade deficit against Turkey.
- iv. The petitioner wants to protect its market dominance and monopolistic position against fair priced products.
- v. There is no factual basis for claiming post invoicing discounts. No evidence has been provided by the petitioner in support of the same.
- vi. The claim on over invoicing amounts to mis-declaration of value which is required to be examined in accordance with Section III of Customs Act, 1962 and the related procedures or under the relevant provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and not under anti-dumping.
- vii. The only basis for claim of post invoicing discount is that the product imported from South Africa is higher than that of the DI. There are a number of factors where imports are to be made including quality consideration, inability of the domestic industry to supply the product etc. In fact, DG Safeguards noted instances where domestic industry was not able to supply the required quantities and quality of sodium dichromate to the customers.
- viii. The production capacity as stated by the petitioners is wrong as it includes the total capacity of the petitioners wherein other products are also produced. The petitioner can only sell limited quantities of the product. As can be seen in the Pollution control board consent order and considering the capacities mentioned therein, the petitioner can actually produce about 54 MT of the product per day. Total domestic sales in the merchant market during the POI were 13,853 MT. Thus, there is no further scope to increase its domestic sales of sodium dichromate to meet the total domestic demand. Information provided in the petition regarding volume parameters and the volume information disclosed in the Final findings issued by DG Safeguards vary for the period 2013-14.

E.3 Examination by the Authority

18. Various submissions made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:
 - i. As regards the issue of implementation of adjustment plan provided in the safeguard investigation, the domestic industry has submitted that they continued to suffer injury, however, the domestic industry is in process of implementing the adjustment plan as brought before the Safeguard Authority. In the Safeguard findings dated 15th January, 2015, the domestic industry laid down the adjustment plan with regard to the deduction in cost of production by introduction of an alternate CO₂ acidification process. However, the domestic industry submitted before the Safeguard Authority that with the imposition of Safeguard duty, their production and capacity utilization would increase which will lead to reduction in overheads cost leading to further decline in cost. The Safeguard Authority has arrived in its findings after examination of the views of the interested parties that the adjustment plan submitted by the domestic industry is without any time frame for implementation of its CO₂ acidification process so as to show that the domestic industry would adjust to the competition from the foreign suppliers. However, the Safeguard investigation was terminated in view of absence of causal link and other factors required for recommendation of safeguard duty.
 - ii. The domestic industry had submitted that they would focus on cost reduction by introduction of an alternate CO₂ acidification process and in the process of implementation of adjustment plan the domestic industry has been able to install CO₂ acidification plant and trial is being undertaken. However, the CO₂ recovery plant is still to install. The domestic industry has further submitted that complete installation and stabilization of CO₂ acidification and recovery process will take at least 2 years, as a cost cutting measure under the adjustment plan. It is noted that the alleged adjustment plan as suggested in the safeguard findings, could have made domestic industry more cost effective. However, the domestic industry has submitted that under the AD Rules, the Authority is required to consider the domestic industry as it exists and examine whether the performance of the domestic industry deteriorated over the injury period, if any, due to dumped imports from specific sources, unlike safeguard duty investigation which constitute all imports of the subject goods from all

- source. The performance of the domestic industry has, accordingly, been examined based on the information available before the Authority.
- iii. As regards the argument that dumping measures are likely to imbalance the trade deficit against Turkey, it is noted that the trade between nations is encouraged at a fair and competitive price.
 - iv. As regards the argument that the petitioner is trying to monopolize and protect its market position, it is noted that there are other producers in the market and two of them have also supported the application. Further, it is noted antidumping measure, if imposed, it is only after complete examination and analysis of the information on record that dumping is causing injury to the domestic industry. In any case, imposition of anti-dumping duty does not restrict imports, but the users will have the broader choice and liberty to import the subject goods at fair prices from undumped sources which will render better competition in the market.
 - v. As regards the argument regarding the capacity of the domestic industry as evidenced from the pollution control board and the focus on downstream products by the domestic industry, the Authority has examined the consent order of the pollution control board. Vishnu chemicals has claimed actual installed capacity of 70,000 MT per annum (210 MT per day) for Vizag plant, in addition to this there was an additional capacity of 16000 MT in Bhilai plant (Chhattisgarh). But domestic industry has informed that there was no production in Bhilai plant since 2015-16. It is noted that Andhra Pradesh Pollution Control Board (APPCB) vide their order No. 7301/PCB/ZO-Vsp/Tech/2012 -58 dated 23/04/2012 had given the consent to M/s Vishnu Chemicals to produce Sodium Dichromate @120 MTPD only. Considering the 333 working days in a year, capacity for Sodium Dichromate works out to 39960 MT Per Annum. This capacity was revised to 210 MT of Sodium Dichromate per day by the APPCB vide consent order dated 20/06/2016. Based on the above, the Authority has considered the enhanced capacity for Sodium Dichromate w.e.f 20.06.2016 and which works out to be 63,360MT during the POI.
 - vi. Further, petitioner has submitted that the production of subject goods in Bhilai, which had the capacity to produce subject goods to the tune of 16,000MT, was suspended during 2015-16 on account of lack of available domestic market in view of import of subject goods taking away the share of domestic market. Thus, lack of capacity for the merchant sales of sodium dichromate or the focus of the domestic industry on downstream market is causing injury as contended by the opposing interested parties does not hold merit. Further, in any case, assuming that the capacity available with the domestic industry for merchant sales is less than the demand prevailing, it is noted that the demand supply gap does not justify dumping of subject goods. The imports needs to be made at fair prices.
 - vii. As regards the argument of difference in figures of sales, captive consumption, production etc. the domestic industry has submitted that the same information has been provided for the period 2013-14 to the safeguard authority also which has been submitted in this investigation. In support of this, the domestic industry has filed the cost audit report for this period. Based on the information of the Cost Audit Report, It is noted that the combined figure of sales and the captive consumption as per the cost audit report does tally to the extent with the combined figure of sales and captive consumption as disclosed in the safeguard finding. However, the individual figure for the captive consumption and sales disclosed in the safeguard finding do vary with the figures reported in the cost audit report of the domestic industry. With regard to such difference, the domestic industry has submitted that the domestic sales in the safeguard investigation was considered as captive transfers from Vishakhapatnam to Bhilai Plant, whereas domestic sales in this investigation consider the same as captive consumption. However, the minute difference is still there due to the reason that closing transfer from Vishakhapatnam to Bhilai has been treated as domestic sales in the safeguard investigation, however, the same has been considered as inventory in AD investigation, as claimed by the domestic industry. Similarly, it has been seen that the domestic industry has reported the sales of other producers as 8,500 MT for the period 2013-14 before the Safeguard Authority, however, the safeguard authority has reported the volume of other Indian producers as 6,850 MT, which leads to the difference in computation of demand for the same period. However, the Authority has considered the information available before it for the purpose of both dumping & injury analysis in this Anti-dumping Investigation.
 - viii. As regards the difference in import figures for the year 2013-14 as reported in safeguard findings and the petition filed with DGAD for the present investigation, it is submitted by the domestic industry that the data so used in the safeguard finding was DGCI&S published data whereas the data used by the domestic industry in the present investigation is transaction wise DGCI&S import data. Since, the sources of the figures stated in present petition and the safeguard finding is different, there is a little difference in the figures also. In this investigation, the Authority has relied on the transaction wise import statistics obtained from DGCI&S for the POI and preceding three years for the purpose of dumping and injury examination.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

19. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:-

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*
 - (a) *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

F.1 Submissions made by the Domestic Industry

20. Following submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation :

- i. Normal value means the price of the subject goods in the domestic market of South Africa, Kazakhstan, Turkey and Russia. Efforts were made by the petitioners to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of the subject countries. However, the petitioner has not been able to get any information/evidence of price of subject goods in the domestic market of the subject countries.
- ii. Petitioner has determined normal value in the subject countries on the basis of best estimates of cost of production in the subject countries, considering major raw materials prices as per DGCI&S published data and consumption norms of the petitioner and power prices as prevailing in the respective subject country.
- iii. None of the responding exporters have made any public claim that the dumping margin in their response is de minimus. This means a tacit acceptance of unfair dumping having been resorted to by these foreign producers.
- iv. The petitioner has relied upon the transaction wise import data procured from DGCI&S and secondary source, to assess the volume and value of subject imports in India.
- v. Authority should determine dumping margin and consequently, price undercutting, and injury margin by considering comparison of weighted average normal value with individual export price as the export price differs significantly in terms of different purchasers and time periods as can be seen from the import statement. Further, all those transactions where the dumping margin, price undercutting and injury margin is negative are required to be excluded for the purpose of these determinations.
- vi. Petitioners are not privy to the actual evidence and therefore cannot be expected to provide the same for calculations of normal value. Petitioners have provided information for normal value based on best available information.

F.2 Submissions made by the other interested parties

21. The submissions made by the opposing interested parties are summarized below:

- i. With regard to the Normal value for Soda Sanayii A.S., Turkey, the exporter has submitted that the normal value should be calculated based on the cost or exports to third countries and not based on the Domestic Sales. Company submitted that the home market sales of PUC are not comparable with its export price to India for the purpose of determining normal value. Home market is a unique market and the sales to distributors/wholesalers are not comparable with the Sales to Indian end-users and end-use of subject merchandise in Home Market is different than the end-use in India. The Indian customers are mostly saccharine producers while there are no saccharine producers in Turkey. In the home market the customers mostly purchase the subject merchandise to be used in paint that avoids wood corrosion. In the view of the same, Soda Sanayii A.S. has requested the Authority to consider cost or export price to third countries for the purpose of determining normal value.
- ii. The Soda Sanayii A.S. exports through an affiliated trader namely Şişecam Dış Ticaret A.Ş. (“\$DT”). The trader exports the goods to India at the same price as that of Soda Sanayii A.S. and being paid a commission at a fixed percentage of the value.

- iii. Petitioner states that the export price from subject countries significantly differs in terms of customer and time period but this does not reflect how and to what extent the prices differ. Due to the lack of substantiation the comparison of the weighted average normal value with individual export price methodology be rejected and the same is incorrect on multiple accounts. The methodology of Zeroing as is claimed by the petitioner is inconsistent and in violation of the AD Rules.
- iv. Since, the exporters from Turkey and South Africa have responded, the normal value may be computed based on their submissions. Also, there is no requirement to claim de minimis dumping margin in the questionnaire response separately.
- v. Since exporters from South Africa and Turkey have responded, therefore, export price and dumping margin should be determined based on the information provided by them.

F.3 Examination by the Authority

22. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:
- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
 - (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);
23. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, barring the following producer and exporters, none of the other producers/exporters from subject countries co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses.
- (i) M/s Lanxess Cisa Pvt. Ltd.(producer) , South Africa
 - (ii) M/s Lanxess (Pty) Ltd (exporter), South Africa.
 - (iii) M/s Soda Sanayii A.S (producer), Turkey
 - (iv) M/s Sisecam Dis Ticaret A.S, Turkey.
24. Since the above mentioned producers/exporters have filed the questionnaire response, the Authority proposes to determine individual dumping margin in respect of these companies. The general methodology adopted by the Authority for determination of Normal Value for these exporters is to first examine whether the domestic sales of the subject goods by the responding exporters in their home markets were representative and viable for permitting determination of Normal Values on the basis of domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the respondents.
25. In the case of non-cooperating exporters in the subject countries, the Authority proposes to determine the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6 (8) of AD Rules read with Article 6.8 of the Agreement.

A) Normal Value

I. South Africa

a) Normal Value for M/s Lanxess Cisa Pvt. Ltd., South Africa

26. The response filed by them was examined. The Authority notes that the company has sold the subject goods in the domestic market, which is not representative to consider for determination of normal value. Even the request to consider the third country export for determination of normal value was not undertaken, since they have provided third country sales information for 30% of exports of subject goods. Since they have not provided complete information of all exports to third country and as per information filed, almost entire exports made to these third countries is at loss, in such situation , normal value cannot be determined based on these exports. The authority has, therefore, determined normal value on the basis of cost of production including SGA and reasonable profit. Accordingly, the normal value has been determined as *** US\$/MT.

b) Normal Value for non-cooperating producers and exporters from South Africa

27. The Authority notes that no other producer/exporter from South Africa has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in South Africa, the Authority has determined normal value as *** US\$/MT as facts available.

II. Turkey**a) Normal Value for M/s Soda Sanayii A.S, Turkey**

28. The response filed by them was examined. The exporter has submitted that the domestic market is peculiar, and the prevailing domestic sales prices are not comparable to the export price to India and the same are inflated on account of end use of the product concern. As a result, the exporter has submitted that normal value may not to be calculated on the basis of domestic sales reported in Appendix 1 and shall be calculated either on the basis of cost or export sales to third countries.
29. The Authority examined the domestic sales and noted that the sales in the domestic market are made in the ordinary course of trade. There is no merit in the argument and also failed to provide evidence to demonstrate that why the price in domestic market should not be considered. The Authority has, therefore, decided to determine the normal value based on domestic sales of the exporter. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. If profit making transactions are more than 80% then the Authority considers all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. In this case, based on the ordinary course of trade test, all domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were more than 80%, the exporter has claimed adjustments on inland freight and credit cost, which have been verified and allowed. Accordingly, the normal value has been determined as *** US\$/MT.

b) Normal Value for other producers and exporters in Turkey

30. The Authority notes that no other producers/exporters from Turkey have responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Turkey, the Authority has determined the normal value as facts available as *** US\$/MT.

III. Kazakhstan**Normal Value for producers and exporters in Kazakhstan**

31. None of the producers/exporters from Kazakhstan filed the response to questionnaire; therefore, the Authority treated them as non-cooperative. In view of non-cooperation from the producers/exporters from Kazakhstan, the Authority is not able to determine individual dumping margin for producers/exporters and is constrained to proceed with the principles of best available information with regard to determination of dumping margin. In view of non-cooperation of the exporters, the Authority determined normal value as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Accordingly, Normal value has been determined as *** US\$/MT.

IV. Russia

32. None of the producers/exporters from Russia filed the response to questionnaire; therefore, the Authority treated them as non-cooperative. In view of non-cooperation from the producers/exporters from Russia, the Authority is not able to determine individual dumping margin for producers/exporters and is constrained to proceed with the principles of best available information with regard to determination of dumping margin. In view of non-cooperation of the exporters, the Authority determined normal value as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Accordingly, Normal value has been determined as *** US\$/MT.

B) Determination of Export Price**i. South Africa****a) Export price for M/s Lanxess Cisa Pvt. Ltd with M/s Lanxess (Pty) Ltd, South Africa**

33. M/s LANXESS (PTY) LTD has filed questionnaire response and during the POI, they have exported 5553 MT of the subject goods to India. They did not report any adjustment beyond ex-factory in Appendix 2, however, month wise adjustments have been reported and claimed in Appendix 3A. M/s LANXESS (PTY) LTD has claimed adjustments on account of Packing, Inland Freight, Cargo Dues, Overseas Freight, and Overseas Insurance. The same have been allowed, after due verification. Accordingly, the Authority has determined the Ex-factory export price as *** US\$/MT.

b) Export price for non-cooperating producers and exporters from South Africa

34. The Authority notes that since no other producers/exporters from South Africa have responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in South Africa, the Authority has determined the net export price as *** US\$/MT as facts available.

ii. Turkey**a. Export price for M/s Soda Sanayii A.S with M/s Sisecam Dis Ticaret A.S, Turkey**

35. M/s Soda Sanayii A.S has filed questionnaire response and during the POI, they have exported 3240 MT of the subject goods to India. They claimed expenses on account of Inland Freight, Ocean Freight, Local expenses, Marine insurance, credit cost, bank charges, Forex gain and Commission to Indian exporter. The same have been allowed, after due verification except the forex gain since it was not substantiated. Accordingly, the Authority has determined the Ex-factory export price as *** US\$/MT.

b) Export price for non-cooperating producers and exporters from Turkey

36. The Authority notes that since no other producers/exporters from Turkey have responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Turkey, the Authority has determined the net export price as *** US\$/MT as facts available.

iii. Russia**Export Price for producers and exporters in Russia**

37. The Authority notes that no producers/exporters from Russia have responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Russia, the Authority has determined the net export price as *** US\$/MT as facts available.

iv. Kazakhstan**Export Price for producers and exporters in Kazakhstan**

38. None of the producers/exporters from Kazakhstan filed response to the questionnaire. Therefore, the Authority treated them as non-cooperative. In view of no cooperation from the producers/exporters from Kazakhstan, the Authority has determined net export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules as *** US\$/MT as facts available.

C) Dumping Margin Table

39. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from the respective subject countries have been determined as provided in the table below:

S. No.	Country	Producer	Exporter	Normal Value – US\$/MT	Export price – US\$/MT	Dumping Margin – US\$/MT	Dumping Margin - %	Dumping Margin Range- %
1.	South Africa	M/s Lanxess Cisa Pvt. Ltd	M/s Lanxess (PTY) LTD	***	***	***	***	15-20
2.	South Africa	All Others	All Others	***	***	***	***	20-25
3.	Turkey	M/s Soda Sanayii A.S	M/s Sisecam Dis Ticaret A.S	***	***	***	***	70-75
4.	Turkey	All Others	All Others	***	***	***	***	80-85
5.	Russia	All	All	***	***	***	***	0-(5)
6.	Kazakhstan	All	All	***	***	***	***	20-25

G. METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**Injury Examination****G.I Submissions made by the Domestic Industry**

40. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation:
- i. The exporters from more than one country are exporting the subject goods and hence as per the rules, the present case is fit for cumulative assessment. The dumping margins and the volumes of exports are more than the de-minimis limits prescribed. The subject goods directly compete with the like products offered by the domestic industry.
 - ii. The demand for the PUC has increased throughout the injury period. Imports occupy a significant share of the Indian Demand. The imports declined from the base year till 2015-16 but increased in the period of investigation and remained above the base year levels showing an increase of 24% from the base year and 57% from previous year.
 - iii. Imports from the subject countries occupy 98% of total import into the country. Figures pertaining to total imports and total demand differ for the reason that the DG safeguard used IBIS data, whereas the petitioner had provided DGCI&S data. Imports in relation to production declined till 2015-16 but surged in the period of investigation. Subject imports in relation to demand followed the same trend and remained around the same levels as compared to the base year.
 - iv. The landed price of the dumped imports is significantly below the selling price of the domestic industry. The level of price undercutting from the subject countries have increased significantly in the POI resulting into significant increase in imports. Price undercutting should be determined only considering those import transactions whose landed price of imports is below the selling price of the domestic industry.
 - v. The cost of production declined from the base year till 2015-16 but increased in the period of investigation. the selling price of the domestic industry also followed the same trend but the decline in prices was more than the decline in the costs; in the POI, whereas the costs increased, the selling price declined; selling price was below the cost of production in the period of investigation; the landed price of imports remained below the cost of production of the domestic industry and hence the imports were suppressing and depressing the domestic industry prices
 - vi. The petitioner has a capacity of 70,000 MT for the product. However, in view of the dumping the petitioner had to close a plant in Bhilai which had a capacity of 16,000 MT. There was minimal production in 2013-14 and was not operational thereafter therefore the capacity of the plant in Bhilai has not been included in the injury information. The addition of the same would show greater decline in production, sales and utilization.
 - vii. Production of domestic industry increased till 2015-16 but declined thereafter in the POI to levels below what was attained in 2014-15 and previous year. The capacity utilization as well as the domestic sales of the petitioner also show the same trend. Market share of the DI, including and excluding captive has declined while that of the subject imports has increased. Despite having enough capacity to cater the Indian Demand, the domestic industry has been losing its market share.
 - viii. Performance in terms of price parameters has deteriorated. Profits remained low up to 2015-16. With the decline in import prices the DI was forced to sell below the cost of sales. Profit before tax and return on investment has declined throughout the injury period.
 - ix. Inventories increased till 2015-16 but declined in the POI, as the domestic industry has reduced its prices in order to compete with dumped imports. Despite this the level of the inventories stayed at levels above 2013-14 and 2014-15.
 - x. Employment and wages have increased in the injury period. Wages paid by the domestic industry has also increased but this is in line with the wage laws in the Country and the same does not reflect the adverse impact of dumping. Productivity of the domestic industry increased till 2015-16 but declined thereafter.

- xi. The overall growth of the domestic industry has also remained adverse. Despite the existence of demand and the ability to cater to that demand, the DI has not been able to do because of the dumped imports.
- xii. Growth in profitability was negative and the DI is suffering financial losses. Efforts were made to improve sales and production and sales were made at prices much below the levels of cost of sales, even then the volume parameters could not take off. The current state of affairs of the DI do not allow for fresh investments.
- xiii. The focus was and still is on the product concerned but only to survive the petitioner was forced to export the subject goods. The domestic industry had significant capacities left unutilized even after utilizing capacity for downstream products.
- xiv. Information on captive consumption in terms of volume and value has been provided to assess the impact of dumped imports on the domestic industry.
- xv. The subject imports declined from 2013-14 till 2015-16, the domestic industry witnessed an increase in sales. When imports of subject goods increased in POI the sales of DI declined. Imports increased by 57% in the POI as compared to previous year and sales of the domestic industry declined by 23% consequently leading to a decline in market share by 26%.
- xvi. Fall in sales of exports of the domestic industry are entirely immaterial as they are not the basis of the injury for the current investigation and the data provided is on the basis of the injury caused to the domestic industry as a result of low priced imports.
- xvii. Petitioner is using imported ore as well as procuring Ore from Orissa Mining Corporation, depending on commercial terms and not just one source of ore is being used. Increase in chrome ore prices holds good for all the producers across the globe and is not a factor relevant only for the domestic industry.
- xviii. The present case is a clear situation where the exporter is dumping the goods into the country at a significant rate and is trying to cover up for the dumping being practiced with the argument on "ordinary course of trade" as none of the situations to prove otherwise exist.
- xix. Imports were at high level and even in 2013-14 because of which Kanakdurga was forced to shut its production in 2014.
- xx. Safeguard petition cannot be a benchmark for non-imposition of duty in the current investigations as the period considered is different. Injury assessment is to be done on an 'as is' basis and based on current data and definitely based on the data of previous injury period. Further, the scheme and scope of antidumping and safeguard law are different.
- xxi. Petitioner has been forced to captively consume the products in view of lack of favourable domestic market due to dumped imports. Because of the high volumes of imports the production of the domestic industry declined and remained low. Domestic sales declined in the POI after increasing till 2015-16. Even after exports and captive consumption, capacity with the DI remained unutilised.
- xxii. There is no correlation between declining sales and demonetisation. Injury is because of increase in imports in the POI with decline in import prices, while the costs increased.
- xxiii. Imposition of duty is not against public interest. Reference made to safeguard investigation is incorrect. Unlike safeguard law, anti-dumping law does not impose duty on all imports. The consumers will be able to source the subject goods from undumped sources without payment of antidumping duty. Even though petitioner is a major producer, it will have to compete with the subject goods coming from undumped sources and therefore cannot abuse its position.
- xxiv. The other known factors viz. export performance, technology, performance of the other products of the company, trade restrictive practices listed in the anti-dumping agreement or in the Rules have not caused injury to the domestic industry.
- xxv. The price suppression/depression effect of dumped imports from subject countries has resulted in significant financial losses to the domestic industry. Significant financial losses have led to deterioration in return on capital employed and cash profits;

- xxvi. Market share of the imports from subject countries remained at a very significant level. The domestic industry could not achieve the optimum levels of production, capacity utilization and sales volumes due to dumped imports.

G.II Submissions made by the other interested parties

41. The following are the injury related submissions made by the other interested parties during the course of the present investigation ;
- i. The petitioner's data on captive consumption and the actual capacity available may be verified. Actual figure of demand including captive consumption should be disclosed.
 - ii. DI has not provided any explanation with regard to difference in figures in the DG safeguard findings and as stated in the petition concerning production of domestic industry, sales of the domestic industry, sales of the other producers and more importantly profit of the of the domestic industry.
 - iii. Exclusion of imports where the domestic industry would have experienced price overcutting over imports is not permitted and is not consistent with Article 3.2 of the Antidumping Agreement. Price undercutting is not alone determinative in an injury determination; rather, it forms part of the overall assessment of injury to the domestic industry and is conducted so as to provide guidance to the investigating authorities in the context of its assessment of injury and causation.
 - iv. With regard to the claims of the DI on the exclusion of those transactions which are not injurious for determination of injury margins it is a consistent practice of the Designated Authority to take all import transactions from a country into account for determination of injury margin. It does not suffice to say such a practice is not challenged in the WTO and hence should be adopted. AD duty can be levied on the injury margin if it is lower than the dumping margin. And in case the claim of the DI is accepted it would imply that there can be no cases where the injury margin is negative and would result in no cases with negative injury margin and no termination of investigation.
 - v. There is an increase in imports due to the increase in demand yet the same did not result in a noticeable increase in market share. It cannot be said that there has been a 'significant' increase in imports.
 - vi. There is no connection between decline in profits and dumped imports. The imports have not hurt the sales of the domestic industry, rather the sales of the domestic industry have increased.
 - vii. No relationship between price undercutting and the profit/loss incurred. Even when the imports were undercutting the prices, the domestic industry was earning profits. Market share of the domestic industry also increased. However, currency devaluation is the major cause of injury. Volatile prices of chrome ore are also a cause of injury.
 - viii. Imports from Kazakhstan do not require cumulative assessment as the product from Kazakhstan is different from that offered by the domestic industry.
 - ix. The production capacity, utilization, total share in production as well as total Indian production has also increased. Production levels were above the demand. There has been an increase in sales volumes.
 - x. Employment and wages have also increased despite the claim of decreased profitability which clearly shows mismanagement.
 - xi. Market share of the petitioners has increased. The ROI declined because of the anticipatory increase in capacity and employment.
 - xii. Indexes for productivity increased from 100 in 2012-13 to 164 in 2015-16 and 138 in 2016-17. The indexed data for stocks declined from 100 in 2013-14 to 86 in 2016-17 and hence shows no injury. The exports of the company declined which is the actual cause of injury and it should not be attributed to imports.
 - xiii. It was submitted on behalf of Kanakadurga that it was forced to shut down in 2014 due to increases in the subject imports. However, between 2013-14 and 2014-15, imports of the PUC actually decreased, and the market share of the domestic industry increased.
 - xiv. No causal link was established between injury and dumping as per previously decided safeguards petition.
 - xv. The sales of the petitioner declined because of the drastic decline in the exports of the petitioner due to increase in captive consumption of the domestic industry.
 - xvi. Injury margin has been calculated by considering only those transactions that are below the non-injurious price. In India, the weighted average to weighted average comparison is used to calculate injury margin which would include all transactions. The Petitioner has mistaken injury determination with injury margin

- calculation. Exclusion of imports where the domestic industry would have experienced price overcutting over imports is not permitted and is not consistent with Article 3.2 of the Antidumping Agreement.
- xvii. Selling price was above cost of production and domestic industry made profit till the year 2015-16 on the sale of sodium dichromate as well. Cost of production and selling price has increased commensurately in the POI. Decline in profit of PUC as claimed by the DI is unreliable.
- xviii. Public interest needs to be examined as this would lead to the petitioner being the only player in the market and higher costs of the product. Issue of public interest was analysed in the safeguard finding also and may be computed on the basis of the lesser duty rule.
- xix. DI has failed to provide actual data regarding captive consumption of sodium dichromate as distinguished from data relating to the merchant market. The distinction between the two is relevant because production destined for captive use is not exposed to direct competition from imports.
- xx. It is not possible that profits on dichromate declined by 82% in 2015-16 as compared to previous year and that the profit on derivatives increase during the same time. The imports also declined in the same period and so they could not be a cause of injury.
- xxi. Vishnu chemicals reported losses in the year 2013-14 for the PUC as per the information submitted to DG Safeguards and disclosed in the final findings. However, in the petition Vishnu chemicals is showing profit for the year 2013-14 for the PUC.
- xxii. Distinction between captive and merchant market is relevant for injury analysis because production (by domestic industry) destined for captive use are not exposed to direct competition from imports. The domestic industry has failed to provide actual data regarding captive consumption of sodium dichromate as distinguished from data relating to the merchant market.
- xxiii. Production and sale of sodium dichromate is regulated as per the consent order issued by state pollution control board. The consent order provides for installed capacity of several products for Vishnu Chemicals as below:

Name of the product	Capacity
Sodium Dichromate	210 tons/day
Basic chromium sulphate	180 tons/day
Chromic acid	40 tons/day

- Basic chromium sulphate and Chromic acid are derivatives of sodium dichromate. 0.5 MT of sodium dichromate gives 1 MT of Basic chromium sulphate (BCS). 1.65 MT sodium dichromate gives 1 MT of chromic acid. Thus, 90 MT per day of sodium dichromate will be used in producing 180 MT of BCS per day and 66 MT per day of sodium dichromate will be used in producing 40 MT of chromic acid per day. Accordingly, 156 MT of sodium dichromate per day will be required for captive consumption.
- xxv. Sodium dichromate available for merchant market is only 54 MT per day (i.e. 210 MT per day – 156 MT per day). Total capacity for merchant market is 17,820 MT approximately (i.e. 54 MT * 330 days). If Vishnu Chemicals operates at 80% capacity utilization, it would be able to produce 14,256 MT of sodium dichromate which would be available for merchant market.
- xxvi. Total domestic sales in the merchant market during the POI were 13,853 MT. Thus, there is no further scope to increase its domestic sales of sodium dichromate to meet the total domestic demand.
- xxvii. Vishnu chemical has monopoly in production and sale of sodium dichromate in the domestic market. Imposition of duty on import of sodium dichromate will make imports unviable for the downstream industry. The downstream industry will have no choice but to purchase sodium dichromate from the monopolistic supplier who is also a competitor. This would give undue advantage to one large scale domestic producer at the cost of several small scale industries.
- xxviii. Sodium dichromate is used in wide variety of industry and applications including metal finishing industries, anti-corrosive applications, water treatment chemicals, pigments, paints, chromium chemicals, pharmaceuticals (ibuprofen), textiles (mordant for acidic dyes) etc. Thus, anti-dumping duty will impact wide variety of downstream industries.

G.III Examination by the Authority

42. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and examined the various parameters in accordance with the Anti-dumping Rules and considered the submissions made by the interested parties.

H. Cumulative Assessment

43. Para (iii) of Annexure II of the Anti-dumping Rules provide that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article and
- b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles

44. The Authority notes that:

- a) The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
- b) In view of the de-minimis dumping margin from Russia, AD investigation against them has been terminated. Therefore, the subject countries in this investigation now constitute only South Africa, Kazakhstan and Turkey. Accordingly, volume of imports from these subject countries have been taken for the purpose of injury analysis.
- c) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
- d) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

45. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.

46. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-dumping Rules.

47. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as below.

I. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry**(a) Assessment of Demand/Apparent Consumption**

48. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed shows increase throughout the injury period, as is given in the table below. The demand has increased throughout the investigation period as compared to the base year.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Demand-Excluding Captive Consumption					
Domestic industry sales	MT	10,822	13,972	17,938	13,853
Other producers sales	MT	8,500	8,500	8,500	8,500

Subject imports	MT	6,046	5,507	4,869	11,360
Other imports	MT	6,565	4,924	4,809	5,044
Demand/consumption	MT	31,933	32,904	36,143	38,758
Demand-Including Captive Consumption					
Domestic industry sales	MT	10,822	13,972	17,938	13,853
Captive Consumption	MT	18,447	24,097	26,582	25,740
Other producers sales	MT	8,500	8,500	8,500	8,500
Subject imports	MT	6,046	5,507	4,869	11,360
Other imports	MT	6,565	4,924	4,809	5,044
Demand/consumption	MT	50,380	57,001	62,725	64,497

(b) Import Volumes from subject countries

49. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in imports from subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. It is noted that the product under consideration imported from Kazakhstan, Russia and Turkey are in anhydrous form whereas the imports from South Africa and the goods produced by the domestic industry is of dehydrate form. The volume of imports of anhydrous form of subject goods have been converted into the volume in di-hydrate form taking into account the standard moisture content in each of the forms. Accordingly, the volume of imports of the subject goods in dihydrate form from the subject countries has been analyzed as under:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Kazakhstan	MT	2,477	886	909	2,909
S. Africa	MT	3,000	4,144	2,418	5,224
Turkey	MT	568	477	1,568	3,227
Subject countries	MT	6,046	5,507	4,869	11,360
Other Countries	MT	6,565	4,924	4,809	5,044
Total Imports	MT	12,611	10,432	9,705	16,405

50. It is seen that imports of the subject goods from the subject countries in absolute terms have increased during the POI. The imports from the subject countries have shown significant increase during the period of investigation as compared to the previous year. The imports showed a decline from 2014-15 till 2015-16 but increased significantly in the period of investigation. However, Domestic industry had submitted that the decline in volume of imports during 2014-15 and 2015-16 was mainly due to the apprehension of imposition of safeguard duties pursuant to the safeguard investigation.

(c) Subject Country Imports in relative terms

Particular	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Subject Country Import in relation to Production	%	20.77	14.11	10.72	29.41
Subject Country Import in relation to Demand (With Captive)	%	12	9.66	7.80	17.61
Subject Country Import in relation to Demand (Excluding Captive)	%	32.77	22.86	18.42	44.14

51. It is seen that the subject imports in relation to production declined till 2015-16 but increased in the POI. The subject imports in relation to demand also dropped till 2015-16 in both captive and without captive but increased sharply in the POI.

(d) Share of subject imports in total imports

Particular	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Kazakhstan	%	19.64	8.50	9.37	17.73
S. Africa	%	23.79	39.72	24.92	31.84
Turkey	%	4.51	4.58	16.16	19.67

Subject countries	%	47.94	52.80	50.44	69.25
Other Countries	%	52.06	47.20	49.56	30.75

52. It is seen that the share of dumped imports from subject countries in imports of the product under consideration in India is around 69.25% of the total imports into the country.

(e) Market Share in Demand

53. Considering imports from various sources and sales of the domestic industry, market share of subject imports in demand in India was examined. The Authority notes that the market share of the subject imports decreased till 2015-16 but increased significantly in the POI whereas market share of the domestic industry increased till 2015-16 and declined steeply thereafter in the POI.

Particular	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Domestic industry (without captive)	%	33.89	42.46	49.63	35.74
Other Indian Producers	%	26.62	25.83	23.52	21.93
Subject imports	%	18.93	16.74	13.54	29.31
Other imports	%	20.56	14.97	13.31	13.02
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00
Domestic industry(with Captive)	%	58.10	66.79	70.98	61.39
Other Indian Producers	%	16.87	14.91	13.55	13.18
Subject imports	%	12	9.66	7.80	17.61
Other imports	%	13.03	8.64	7.67	7.82
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.0

J. Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

54. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with weighted average landed cost of imports of the subject goods from the subject countries.

a) Price Undercutting

55. For the purpose of price undercutting analysis the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level is determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

Particulars	Unit	Kazakhstan	Russia	South Africa	Turkey	Subject Countries
Landed Value	Rs./MT	72,896	74,310	78,898	73,124	75,305
Net Sales realization	Rs./Kg	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	15-20	10-15	5-10	15-20	10-15

S.No.	Country	Producer	Exporter	Landed Value (Rs/MT)	Selling Price (Rs/MT)	Price Undercutting (Rs/MT)	Price Undercutting %	Range
1.	South Africa	M/s Lanxess Cisa Pvt. Ltd	M/s Lanxess (PTY) LTD	***	***	***	***	10-15
2.	Turkey	M/s Soda Sayani A.S	M/s Sisecam Dis Ticaret A.S	***	***	***	***	15-20

56. Price undercutting from the subject countries in POI are positive.

b) Price Suppression and Depression

57. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Cost of production	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	90	88	95
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	93	87	92
Landed Value	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		100	94	89	82

58. From the above, it is noted that both selling price as well as cost of production of the domestic industry has declined in POI as compared to the base year. The selling price in POI is below the level of cost of production. It is also noted that the landed price of imports in POI declined significantly as compared to the decline in costs in POI as compared to base year. Thus, imports are not only depressing but also suppressing the prices of the domestic industry.

c) Price Underselling

59. The non-injurious price (NIP) of the domestic industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The NIP has been determined considering optimum level of capacity utilisation that the petitioner can achieve in the plant. Further, the actual level of raw materials and utilities consumption has been considered taken as optimum norms for the product of the domestic industry. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports were above the non-injurious price of the domestic industry, as can be seen from the table below, demonstrating negative price underselling effect:

S.No	Country	Producer	Exporter	Landed Value (Rs/MT)	NIP (Rs/MT)	Injury Margin (Rs/MT)	Injury Margin %	Range
1.	South Africa	M/s Lanxess Cisa Pvt. Ltd	M/s Lanxess (PTY) LTD	***	***	***	***	(10-15)
2.	Turkey	M/s Soda Sayani A.S	M/s Sisecam Dis Ticaret A.S	***	***	***	***	(5-10)
3.	South Africa	All Others	All Others	***	***	***	***	(5-10)
4.	Turkey	All Others	All Others	***	***	***	***	0-(5)
5.	Russia	All	All	***	***	***	***	(5-10)

<u>S.No</u>	<u>Country</u>	<u>Producer</u>	<u>Exporter</u>	<u>Landed Value (Rs/MT)</u>	<u>NIP (Rs/MT)</u>	<u>Injury Margin (Rs/MT)</u>	<u>Injury Margin %</u>	<u>Range</u>
6.	Kazakhstan	All	All	***	***	***	***	(5-10)

60. It is noted that the landed prices of the imports from the subject countries are much above the Non-Injurious prices of the domestic industry thereby resulting in negative price underselling.

K. Economic Parameters of the Domestic Industry

61. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

62. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

(a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

63. Capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry over the injury period is given in the following table:-

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Plant capacity	MT	39,960	39,960	39,960	63360
Production	MT	29,105	39,029	45,675	38,624
Captive Consumption	MT	18,447	24,097	26,582	25,740
Capacity Utilization	%	73%	98%	114%	60.96%
Captive Consumption to total Production	%	66.38%	61.74%	58.19%	66.64%
Sales	MT	10,822	13,972	17,938	13,853
Sales to total Production	%	37.18%	35.80%	39.27%	35.86%

(capacity @120MTPD till 19.06.2016 and @210MTPD from 20.06.2016, for 333 operating days in a year)

64. It is noted that:

- Vishnu chemicals has claimed actual installed capacity of 70,000 MT per annum (210 MT per day). In addition to this there was additional capacity of 16000 MT in Bhilai plant (Chhattisgarh). But domestic industry has informed that there was no production in Bhilai plant since 2015-16. Therefore, this plant has not been considered for NIP workings. Andhra Pradesh Pollution Control Board (APPCB) vide their order No. 7301/PCB/ZO-Vsp/Tech/2012 -58 dated 23/04/2012 had given the consent to Vishnu Chemicals to produce 120 MTPD only of Sodium Dichromate. Considering the 333 working days in a year capacity for Sodium Dichromate works out to 39960 MT Per Annum. This capacity was revised to 210 MT of Sodium Dichromate per day by the APPCB vide consent order dated 20/06/2016. Based on the above the Authority has considered the enhanced capacity for Sodium Dichromate w.e.f 20.06.2016.
- The production of the domestic industry increased from the base year till 2015-16 and declined during the POI. Capacity utilisation also follows the same trend. Interested parties have argued that the focus of the domestic industry is on downstream products. Further it is seen that the captive consumption has increased over the injury period and captive consumption was 66.64% during POI. Domestic Industry has submitted that despite the inclusion of captive consumption, they are not able to utilize its full potential and achieve the desired capacity utilization levels. However, the authority finds that the capacity utilization was restricted due to restriction imposed by APPCB.
- Since the company could only produce within the production ceiling recommended by the APPCB, the installed capacity considered by DGAD for NIP working is 39,960 MT per annum up to 20.06.2016 and about 70,000MT per annum thereafter.

- d) The domestic sales of the petitioner have not followed the same trend as that of the production. Increase in production during injury period has not resulted into increase in domestic sales in the same ratio. It is seen that while there was a decline in imports, the sales of the domestic industry increased and when the subject imports increased in the period of investigation, the domestic sales again declined to below 2014-15 levels. It is noted that the domestic sales have remained low throughout the injury period.

(b) Profitability, return on investment and cash profits

65. Vishnu chemicals reported losses in the year 2013-14 for the PUC as per the DG Safeguards final findings. However, in the present ADD petition Vishnu chemicals showing profit for the year 2013-14 for the PUC. Petitioner has stated that in the safeguard petition information was provided considering the expenses as whole including the Bhilai plant whereas in the present petition profitability of Vizag plant for PUC has been claimed by the domestic industry.

66. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:-

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Profit/loss - Domestic	Rs.Lacs	***	***	***	***
Indexed		100	394	37	(193)
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Indexed		100	165	101	47
ROCE	%	***	***	***	***
Indexed		100	149	117	45

67. Following is noted from the table above:

- Subject imports increased in the POI at significantly low price and in a bid to compete with such imports, the domestic industry was forced to reduce its selling price in order to match which went below the levels of cost of sales in the POI and hence, the domestic industry suffered losses.
- The cash profits increased in 2014-15 but declined in 2015-16 and further declined in the POI. The same trend can be seen for the return on capital employed which increased till 2014-15 but showed a downward trend from the 2015-16 and declined further in the POI to levels much below those achieved in the base year.

(c) Market Share in Demand

68. Market share of the domestic industry in demand for the product under consideration is given in the table below:

Particular	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Domestic industry (without captive)	%	33.89	42.46	49.63	35.74
Other Indian Producers	%	26.62	25.83	23.52	21.93
Subject imports	%	38.36	30.90	26.74	41.55
Other imports	%	1.14	0.80	0.11	0.77
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00
Domestic industry(with Captive)	%	58.10	66.79	70.98	61.39
Other Indian Producers	%	16.87	14.91	13.55	13.18
Subject imports	%	24.31	17.84	15.41	24.97
Other imports	%	0.72	0.46	0.06	0.47
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

69. It is seen that market share of the domestic industry increased till 2015-16 when the import volumes were on a decline but declined in the POI when the subject imports increased.

(d) Employment, productivity and wages

70. Employment, productivity and wages over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
Indexed		100	111	115	115
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Indexed		100	154	163	160
Productivity per day	MT	***	***	***	***
Indexed		100	134	157	133
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Indexed		100	121	136	115

71. It is noted that the employment level have increased over the injury period and wages paid have also increased.

72. Productivity per day and productivity per employee, both, increased till 2015-16 and declined in the POI in consonance with the movement of the production of the domestic industry.

(e) Inventories

73. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Indexed		100	168	123	186
Closing	MT	***	***	***	***
Indexed		100	182	275	98
Average	MT	***	***	***	***
Indexed		100	114	185	151

74. It is noted that the inventories with the domestic industry increased till 2015-16 but declined thereafter. However, the level of inventory remains significant.

(f) Growth

75. Growth of the domestic industry with regard to profits, return on investments, production, capacity utilisation and cash flow has been negative.

Sl. No.	Growth	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	Production	%		34%	17%	-15%
2	Domestic Sales Volume	%		29%	28%	-23%
3	Capacity Utilization	%		25%	16%	-53%
4	Selling price domestic	%		-7%	-6%	6%
5	Profitability	%		205%	-93%	-768%
6	Cash Profit	%		65%	-39%	-54%
7	Return on capital employed	%		1%	-1%	-2%

(g) Ability to Raise Capital Investments

76. Domestic Industry claimed that the current state of its financial position does not allow them to raise capital for fresh investment.

(h) Factors affecting domestic prices

77. The demand for the product has seen a steady growth throughout the investigation period and the only factors which seem to be affecting the domestic prices are the costs of production and import prices.

(i) Magnitude of dumping margin

78. The dumping margin from the subject countries are not only more than de-minims but also substantial, except in case of Russia where the dumping margin is de-minims.

L. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

79. The Authority has determined Non Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been considered for comparing the landed price from each of the subject countries for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III and being followed. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries to determine the injury margin as follows;

<u>S.No</u>	<u>Country</u>	<u>Producer</u>	<u>Exporter</u>	<u>Landed Value (Rs/MT)</u>	<u>NIP (Rs/MT)</u>	<u>Injury Margin (Rs/MT)</u>	<u>Injury Margin %</u>	<u>Range</u>
1.	South Africa	M/s Lanxess Cisa Pvt. Ltd	M/s Lanxess (PTY) LTD	***	***	***	***	(10-15)
2.	South Africa	All Others	All Others	***	***	***	***	(5-10)
3.	Turkey	M/s Soda Sayani A.S	M/s Sisecam Dis Ticaret A.S	***	***	***	***	(5-10)
4.	Turkey	All Others	All Others	***	***	***	***	0-(5)
5.	Russia	All	All	***	***	***	***	(5-10)
6.	Kazakhstan	All	All	***	***	***	***	(5-10)

It is noted that the landed prices of the imports from the subject countries are much above the Non-Injurious prices of the domestic industry thereby resulting in negative injury margin.

M. Causal Link and other factors

80. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry. Accordingly, the following parameters have been examined:

- i. **Volume and value of imports from countries other than the Subject Countries**—Imports from countries other than the subject countries are not causing injury as either the volume is de-minimis or the price is higher.
- ii. **Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption**—The Authority notes that despite increased demand for the subject goods in the country, the domestic industry has faced with unutilized capacity during the POI. There is no change in the pattern of consumption of the subject goods which would have adversely impacted the domestic industry. Possible contraction of demand or changes in the pattern of consumption could not have caused injury to the domestic industry.
- iii. **Development in Technology**—None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry. The petitioner set up a plant for production of the PUC and there is no evidence that the technology adopted by the petitioner could be a cause of injury to the domestic industry.
- iv. **Trade restrictive practices and competition supply from various sources**—The Authority notes that the subject goods are not subjected to any trade restrictive practices in India. Moreover, apart from the

competition that is obvious in any market economy, no inter se competition or competition between supplies from various domestic and international sources exhibit any such impact that could be construed as injurious to the domestic industry.

- v. **Export performance**—The domestic industry does not have significant exports of subject goods. However, the performance of the domestic industry has been segregated for domestic and export market. Therefore, any possible decline in export performance may not be a cause of injury claimed by the domestic industry.

N. Factors establishing causal link—

81. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is not established on the following grounds—
 - a.) Net Sales Realization of the domestic industry is higher than the Non Injurious Price of the domestic industry.
 - b.) The Selling price of the domestic industry is higher than the landed value of imports from the subject countries.
 - c.) The landed value from subject countries is higher than the non-injurious price of the domestic industry.

O. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

82. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and have been addressed appropriately at appropriate places. Additional submissions have been analysed as under:

O.I Submissions by Domestic Industry

83. The submissions made by the domestic industry post-disclosure and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a) The domestic industry has requested the Authority to disclose the non-confidential version of the verification report of the exporters/producers from subject countries to enable domestic industry to offer meaningful comments on the dumping. Domestic industry has also requested to provide the copy of the Communications sent by the Authority and copy the replies filed by the interested parties.
 - b) The domestic industry had stated about the implementation of an adjustment plan which would have led to an increase in production and capacity utilization and a reduction in overheads cost leading to further decline in cost. The same was proposed at the time of the safeguard investigation. However, the safeguard duties were not imposed and despite not having been provided a level playing field through imposition of the safeguard duties, the domestic industry, while continuing to suffer injury, still made efforts for the implementation of the adjustment plan. The domestic industry has installed CO₂ acidification plant and the same has gone through a trial run. Since the adjustment plan is a two stage process, the second stage of the process viz the installation of CO₂ recovery plant is yet to be taken up and it is expected to be taken up in about 2 years. Under the AD Rules, the Authority is required to consider the domestic industry as it exists and examine whether the performance of the domestic industry has deteriorated over the injury period due to dumped imports from specific sources as against all imports of the subject goods from all sources under safeguard duty investigation.
 - c) The capacity has been considered by the Designated Authority on the basis of the APPCB order No. 7301/PCB/ZO-Vsp/Tech/2012 -58 dated 23/04/2012. However, the subsequent clarification provided by APPCB vide Letter no 1475/PCB/RO-VSP/2014-3628 dated 23/07/2014 has not been appropriately considered. The domestic industry has requested that the total capacity (both captive and merchant sales) of the domestic industry be considered as 70,000 MT during the entire injury period including POI. The domestic industry has also stated that the net fixed assets of the Vizag SDC plant are showing a reduction (due to charging of depreciation) and not increase. This further shows that there is no capacity addition. The APPCB has merely clarified the capacities that can be used for merchant sales and captive consumption for another downstream product.
 - d) The disclosure statement considers incorrect figures for the capacity of the petitioner for the period from 2013-14 to 2015-16 and the domestic industry has made submissions vide letter dated 28th May, 2018 with regard to capacity of the plant that should be considered for the present purposes. The capacity reported vide PCB certificate No. 7301/PCB/ZO-Vsp/Tech/2012 -58 dated 23/04/2012 excluded capacity required for captive consumption whereas the PCB order dated 20/06/2016 reports the capacity including captive requirements. The PCB certificate dated 23/04/2012 which showed capacities excluding captive consumption, the PCB certificate was since then clarified vide document dated 23rd July 2014, wherein it was clarified that

the domestic industry has a manufacturing capacity of 210 MTPD but a saleable quantity of the concerned product to the tune of 120 MTPD which makes the capacity to produce subject goods as 70,000 MT (including for captive consumption). The said clarification was filed by the petitioner vide our letter dated 22nd May 2018 which has been completely ignored. Evidently, the capacity of 120 MT mentioned in the said letter is excluding 90 MT Sodium Dichromate that company can produce for production of Basic Chrome Sulphate. Production of one MT of basic bichrome sulphate requires 0.50 MT of sodium Dichromate. Petitioner has a capacity of 180 MT basic bichromate sulphate for which petitioner requires 90 MT sodium Dichromate. Thus, vide this letter from pollution control board considered 120 MT Sodium Dichromate for sale and 90 MT sodium Dichromate for consumption in production of basic chrome sulphate.

- e) It is stated that in any case, if capacity is considered excluding captive consumption, then production must also be considered after excluding captive consumption. While capacity upto June, 2016 excludes capacity for captive consumption, production considered includes production for captive consumption. It is inappropriate to consider capacity excluding captive consumption and production including captive consumption. Capacity utilization will show consistent increase if captive consumption is excluded from production. Thus, there can be no normation for capacity utilization for NIP determination.
- f) The domestic industry has stated that the dumping margin from all the subject countries, as arrived at by the Authority, is positive and above de minimis levels. However, it appears that the constructed normal value has been determined on the basis of NIP determined for the domestic industry. As submitted above, the NIP of the domestic industry is required to be modified for the reasons explained above. Once NIP of the domestic industry is revised, the CNV would also need to be revised.
- g) The domestic industry is suffering injury on account of dumped imports from subject countries as the demand with or without captive consumption has increased throughout the injury investigation period. Secondly, the import volumes declined from 2013-14 till 2015-16 but increased significantly during the period of investigation. This decline in subject imports was because of the apprehension of the imposition of the safeguard duties. In addition to it, the import volumes declined from 2013-14 till 2015-16 but increased significantly during the period of investigation.
- h) The dumped imports have been undercutting the prices of the domestic industry. The selling price as well as the cost of production of the domestic industry declined in the POI in comparison to the base year, but the decline in the selling price has been much more than the decline in the cost of production. The Landed price of the subject imports declined throughout the injury investigation period and was at its lowest level in the POI. Resultantly, the subject imports have had a price depression and suppression effect on the domestic industry prices.
- i) The capacity of the domestic industry has been wrongly determined as is submitted above. The misinterpretation of the APPCB orders has led to consideration of incorrect capacities figures, thereby affecting the capacity utilization, which in turn reflected upon NIP. The Designated Authority is requested to reconsider the workings and calculations for the capacities of the domestic industry as the current capacities as determined by way of the disclosure statement show an incorrect picture of the domestic industry.
- j) The domestic industry has submitted that despite a majority of the economic parameters showing an impact of the dumping and the company suffering negative growth, misinterpretation of the APPCB orders has resulted in miscalculation of the capacity levels and consequently the NIP and injury margin.
- k) Domestic industry has submitted that anti-dumping duty should be imposed in terms of US\$. Rupee has depreciated significantly and therefore, the definitive duties may kindly be expressed in US\$. The depreciation of INR has impacted the costs of the raw materials, utilities and other costs. This is also supported by the rationality involved in the decision of the CESTAT in the matter of Metcoke from China. While converting the duty to US\$, the Hon'ble CESTAT stated as follows:—

“Section 9A stipulates that anti-dumping duty shall not exceed dumping margin. Thus the law's intention and purpose is to afford a protection to the domestic industry at rates not exceeding the dumping margin and injury margin. We are, therefore, of the firm opinion that anti-dumping duty should be fixed in dollar terms so that erosion of the quantum of protection does not take place on account of changes in the exchange rate. In the present case the appellant domestic industry has shown that the level of protection has fallen from over 19 US \$ at the time of final finding to over 16 US \$ by now, on account of depreciation of Indian Rupee against US \$. This is necessary to carry into effect the purpose of anti-dumping duty and is, therefore, fully in conformity with the law.”

O.II Submissions by exporters and other interested parties

84. The following submissions have been made post-disclosure by the Exporters, Importers, Users and other Interested Parties:
- i) The M/s Soda Sanayii A.S have stated that their domestic sales should not be considered for determining the normal value. Instead, the Exporters submit that the normal value should be calculated based on third country sales of the Exporters or on cost plus reasonable profit.
 - ii) M/s Lanxess (Pty) Ltd., South Africa has submitted that it has not exported the PUC to India at dumped prices, and the prices to India are bona fide, arms-length commercial market prices. In view of the same, the observation that there has been dumping and the observation of a dumping margin, as also the observation of our client having indulged in price undercutting, is not merited.
 - iii) M/s Aktyubinsk Chromium Chemical Plants, Kazakhstan has submitted that anhydrous form and hydrous form of sodium dichromate are not merely two forms of product under consideration as mentioned in the disclosure statement. The purported conversion of 'anhydrous' form of the product which has negligible moisture as exported from Kazakhstan to the 'Di-hydrate' form as produced by the domestic industry, to bring volume of subject goods and purity therein at same level is not a wise approach and is arbitrary. Molecular weight of anhydrous form of Sodium Dichromate is 261.965 g/mol., and of hydrous form of Sodium Dichromate is 298 g/mol. The Designated Authority has not provided the methodology it has adopted to convert the quantities of anhydrous sodium dichromate to di-hydrate sodium dichromate.
 - iv) M/s Vishnu Chemicals should not be considered as domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the AD Rules, 1995 as the exception of the definition clearly states that the domestic industry should not be the importer of alleged dumped product. However, the petitioner is the importer of crude chrome ore from other countries and is converting the same ore into Hydrous Sodium Dichromate. Since, available raw material is imported from foreign country, the petitioner clearly doesn't constitute Domestic Industry.
 - v) The domestic industry has claimed that it can increase the production volumes and reduce the cost, however, it is apparent from the data submitted by the domestic industry that the number of employees of the DI were reduced in the POI. The production was also low due to which the DI failed to produce the product under consideration cost effectively.
 - vi) It is a matter of record that the DI has been alleging about injury due to dumping of PUC from 2012-2013 as the DI had also approached the Safeguard's authority in the said year. However, it is apparent from the records and data produced by the DI that the sales, production and profits of the DI were increasing year by year and there was no injury to the DI. The mere fact that the sales and production of the DI went down in the POI and increase in the volume of imports does not establish a causal link between injury and subject imports. There were several other factors including captive consumption, non-availability of Chrome Ore, prices of Chrome Ore, inefficiency of the DI to produce PUC cost effectively which should also be considered.
 - vii) The Domestic Industry is incapable of producing the PUC cost-effectively and rather than implementing new technology, the DI intends to remove the competition from the market. Imposition of AD Duty would further increase the prices of the downstream products and would give an unfair and anti-competitive advantage to the DI as the DI captively consumes its PUC and its downstream products would be produced at relative lower costs.
 - viii) It has been submitted that the disclosure statement does not contain any information about available sources of information on the basis of which the DA has determined export price of Kazakhstan products. It also does not specify any sources used by the Designated Authority to determine normal value of products from Kazakhstan.
 - ix) The DA has missed to take into account the fact that M/s Vishnu Company's petition, on the basis of which investigation was initiated, is not supported by sufficient, admissible and reliable evidence. In this regard M/s ACCP is of the opinion that the investigation has been initiated without any consideration of Article 5 of AD Rules.
 - x) It has been submitted that no positive recommendation of anti-dumping duty can be made due to negative margin of injury in respect of imports of subject goods from subject countries. The Designated Authority has determined negative injury margin for all the subject imports from subject countries. Therefore, it is clear that there is no injury to the domestic industry, which is required to be removed. In the anti-dumping investigations, namely (a) Acrylic Fibre from China, Belarus, Ukraine & Peru (b) Non-woven fabric from Malaysia, India, China and Saudi Arabia & Thailand, DA has determined negative injury margin for most of the subject imports, consequently, D.A did not recommend anti-dumping duty on the

imports from subject countries in all these cases and in this case also the same consistent practice may be followed.

- xi) The Designated Authority may provide actual or indexed figures for key economic parameters of the domestic industry namely employment, wages, and productivity per day, productivity per employee, inventory & profit/loss.
- xii) Disclosure of market share of M/s Vishnu Chemicals and other Indian producers also confirms that Vishnu Chemicals is not willing to sell in the domestic market. D.A also observed that production by M/s Vishnu Chemicals constitutes 82% of total production in the POI, however, it only controls 35.74% market share in the POI. Other Indian producers, which constitute 18% of total production controlled 21.93% market share in the POI which clearly shows that M/s Vishnu Chemicals is concentrating on the increasing sales and profits in downstream products of sodium dichromate and not sodium dichromate.

O.III Examination by the Authority

85. It is noted that the comments on Disclosure statement filed by the interested parties are primarily reiterations and reproductions of their earlier submissions in the context of Disclosure statement. The relevant opposing views and submissions are inter alia addressed under the appropriate sections in this final finding which are self-explanatory based on evaluation of the relevant facts and also in view of the relevant rules and jurisprudences to be followed by the Authority. Nevertheless, certain specific comments on the Disclosure statement raised by the parties are addressed as follows;
- i) With regard to the argument of insufficient information of domestic industry duly filed by them, the Authority notes that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after deriving satisfaction that application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation, decided to initiate the present investigation.
 - ii) As regards the contention that imposition of Anti-dumping duty will have disastrous result on the compounding and downstream industries, the Authority notes that the objective of imposing anti-dumping measure is to rectify unfair trade practices and to redress its injurious effect by providing level playing field to domestic industry. Moreover, imposition of anti-dumping measures, if imposed, does not prevent imports, however imports will be available at fair prices and it will also allow competition in the domestic market.
 - iii) As regards the claim of excessive confidentiality by the interested parties, the Authority notes that it has disclosed the relevant information subject to the claim of confidentiality under Rule 7 of anti-dumping rules, 1995, however, non-confidential versions of the submissions are made available in the public file. However, applicant specific confidential information has been shared with them with regard to dumping margins and non-injurious price.
 - iv) As regards to the concern raised by the interested parties regarding conversion from anhydrous form of product to dihydrate form, it is noted that matter has been examined and deliberated at appropriate para under the heading Product Under Consideration. However, it is reiterated that the conversion has been carried out based on the ratio of the molecular weights of two forms of PUC in order to examine the various parameters at the same level.
 - v) As regards the computation of the production capacity of the PUC, it is noted that this issue has been addressed in detail at appropriate place in this findings. However, it is once again reiterated that based on the information made available before the Authority, both capacity and capacity utilization has been worked out for the purpose of injury analysis in this finding.
 - vi) As regards the determination of constructed normal value, it is noted that it has been worked out taking into account the international price of the raw materials and the consumption norm of the domestic industry for the non-cooperative exporters. The constructed normal value for Russia & Kazakhstan has accordingly been worked out and dumping margin has been modified. In view of the arrived de-minimis dumping margin from Russia, AD investigation against Russia has been terminated. Therefore, the subject countries in this investigation now constitute only South Africa, Kazakhstan and Turkey. Hence, information with regard to the dumping and injury has been modified at appropriate para. However, the normal value has been determined for the cooperative exporters based on the information made available to the Authority.
 - vii) As regards the disclosure of source of information for determination of export price to the non-cooperative exporters, it is noted that transaction wise DGCI&S import data has been considered for determination of export price and injury analysis in this finding.
 - viii) As regards the concern of interested parties regarding their claim of constituent domestic industry, it is noted that based on the information made available before the Authority, M/s Vishnu Chemical has been

considered as the domestic industry as per AD Rules, as they are not the importers of subject goods during the POI.

- ix) As regards the disclosure of index figure, it is noted that wherever it is relevant and appropriate either the volume or the index figure have been disclosed in this findings, keeping the confidentiality of the applicants which otherwise does not impact their commercial interest.

P. Conclusions and Recommendations

86. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:

- I. The product under consideration has been exported to India from South Africa, Kazakhstan and Turkey, below its normal value, resulting in dumping.
- II. The domestic industry has not suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries.
- III. Causal link between imports from subject countries and injury to the domestic industry is not conclusively established.
- IV. In view of the above, the Authority does not consider it appropriate to recommend levy of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject countries and hereby terminates this investigation in accordance with Rule 14(b) (e) and Rule 17 (1) (iii) read with 11(ii) of the Anti-Dumping Rules.

Q. FURTHER PROCEDURE:

87. An appeal against the order of the Central Government arising out of this finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority